बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 23 ● अंक: 167 ● नई दिल्ली ● बुधवार 02 जुलाई 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 8

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाए जाने हेतु सभी बीआरसी कार्यालय पर कैंप का होगा आयोजन

कुशीनगर। मुख्य चिकित्साधिकारी अनुपम भास्कर ने मुख्य विकास अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में बताया कि (संबंधित नोडल अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि स्वयं लाभार्थी को ब्लॉक स्थित बीआरसी कार्यालय ले जा कर दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाना सुनिश्चित करें) कि दिव्यांगजनों का कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण हेतु चिन्हीकरण तथा यूनिक आईडी कार्ड निर्गत हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन प्राप्त करने हेतु व दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने हेतु मेडिकल कैम्प का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु विकास खंड पडरौना बीआरसी कार्यालय पर दिनांक 02.07.2025 को, विकास खंड विशुनपुरा के बीआरसी कार्यालय पर 4 जुलाई को, दुदही बीआरसी पर 7 जुलाई को, सेवरही बीआरसी पर 09 जुलाई को, तमकुहीराज बीआरसी के लिए 11 जुलाई को, फाजिलनगर बीआरसी पर 14 जुलाई को, कसया बीआरसी पर 16 जुलाई को।

दिल्ली में बीजेपी फुलेरा की पंचायत चला रही, इन्हें काम करना नहीं आता, सीएम रेखा गुप्ता के फैसले पर बरसे सौरभ भारद्वाज

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने बीजेपी सरकार द्वारा पुराने वाहनों को पेट्रोल पंपों पर जब्त करने और बारिश के मौसम में कृत्रिम बारिश कराने के फैसले गलत बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। आप के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी को सरकार चलानी नहीं आती है। ये लोग सरकार नहीं, फुलेरा की पंचायत चला रहे हैं। पुराने वाहनों को पेट्रोल पंपों पर जब्त करने से कर्मचारियों और वाहन मालिकों के बीच लड़ाई- झगड़ा होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने सड़कों के गड्ढे भरने का सिर्फ दिखावा किया। छोटे गड्ढे तो भर दिए, लेकिन बड़े गड्ढों को छोड़ दिया। इनको काम नहीं, सिर्फ बहाने बनाने हैं। ये पांच साल सिर्फ बहाने बनाएंगे और केजरीवाल को गालियां देंगे। वहीं, अरविंद केजरीवाल ने हमेशा जनादेश का सम्मान करते हुए काम किया, उन्होंने कभी शीला दीक्षित सरकार का बहाना नहीं बनाया। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने 1 जुलाई से दिल्ली से पुरानी गाड़ियों को हटाए जाने को लेकर मंगलवार को कहा कि भाजपा दिल्ली में सरकार नहीं चला रही, बल्कि वह फुलेरा की पंचायत जैसा प्रशासन चला रही है। यदि पुराने वाहनों को सड़कों से हटाना है, तो क्या इसके लिए कोई और तरीका नहीं मिला? पेट्रोल पंप मालिकों की एसोसिएशन कह रही है कि यह नीति अव्यवहारिक है। सरकार फुलेरा की पंचायत की तरह चल रही है और इन लोगों को न तो सरकार चलानी आती है और न ही ये चला सकते हैं। सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में हो रही रोज की बारिश के बावजूद दिल्ली सरकार के कृत्रिम वर्षा (आर्टिफिशियल रेन) कराने के फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि यह किस तरह के अफसर है,

जिसने तय किया कि मानसून के दौरान दिल्ली में कृत्रिम वर्षा का पायलट प्रोजेक्ट किया जाएगा, जबकि दिल्ली में पहले से ही बारिश हो रही है। फुलेरा की पंचायत के लोग भी इस तरह का अव्यवहारिक फैसला नहीं लेंगे। आम आदमी पार्टी जब सरकार में आएगी, तब इन सभी मामलों की जांच कराई जाएगी।

पांच साल तक बीजेपी वाले सिर्फ केजरीवाल को गाली देंगे : भारद्वाज

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगले पांच साल तक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सिर्फ आप को गाली देती रहेंगी। पांच साल बाद वह यही कहेंगी कि पिछली सरकार में अरविंद केजरीवाल ने ऐसा किया, इसलिए कुछ नहीं हो पाया। जब आप ने शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ा और सरकार बनाई, तब कभी यह बहाना नहीं बनाया कि शीला दीक्षित ने ऐसा किया, इसलिए काम नहीं हो रहा। आप ने हमेशा कहा कि हमें जिस स्थिति में जनादेश मिला, उसका सम्मान करते हुए हम जनता के लिए काम करेंगे।

दिल्ली की मौजूदा बीजेपी सरकार को काम करने की इच्छा नहीं है, वह सिर्फ बहानेबाजी करती है। अगर इनकी सरकार पांच साल चली, तो यह सिर्फ बहाने बनाएगी। सौरभ भारद्वाज ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक आईएएस अधिकारी के साथ मारपीट करने की वायरल वीडियो पर कहा कि दिल्ली में कहा गया कि अंशु प्रकाश को तथाकथित किसी ने थप्पड़ मारा। उस समय उसके ऊपर पूरा जमीन आसमान एक कर दिया गया। अब वे सभी आईएएस अधिकारी कहां छिपे हैं, जो पहले टीवी पर आकर आप और अरविंद केजरीवाल को गालियां देते थे। वे भाजपाई कहां गए, जो अराजकता की बात करते थे। अब क्या होगा? क्या पूरे देश में आईएएस अधिकारी हड़ताल पर चले जाएंगे?

सौरभ भारद्वाज ने आईएएस एसोसिएशन पर भी उठाए सवाल

सौरभ भारद्वाज ने इस मामले को लेकर आईएएस एसोसिएशन पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या आईएएस एसोसिएशन यह मानता है कि वह भी एक राजनीतिक बॉडी है। उन्होंने मनोज तिवारी द्वारा एक आईपीएस अधिकारी का गिरेबान पकड़ने की घटना का जिक्र किया और कहा कि जब मनोज तिवारी ने एक आईपीएस का गिरेबान पकड़ लिया, उस समय आईपीएस एसोसिएशन चुप रही, कोई हड़ताल नहीं हुई, कोई आवाज नहीं उठी। क्या भाजपा ही आईएएस, आईपीएस और अन्य अधीनस्थ सेवा संगठनों को चलाती है? क्या ये सभी संगठन भाजपा के इशारों पर काम करते हैं?

कर्नाटक कांग्रेस में बदलाव की अटकलों पर विराम, सुरजेवाला बोले- नेतृत्व नहीं, कामकाज की हो रही जांच

नई दिल्ली। कर्नाटक कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व में बदलाव को लेकर तेज होती अटकलों पर पार्टी के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने एक बार फिर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मंगलवार को उन्होंने नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा को सिरे से नकारते हुए साफ और स्पष्ट रूप से कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर किसी भी तरह की राय नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में वे केवल विधायकों और सांसदों से उनके क्षेत्रों में किए गए कार्यों की जानकारी ले रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान सुरजेवाला ने कहा कि कल भी मैंने जवाब दिया था और आज भी साफ कर रहा हूं नेतृत्व परिवर्तन को लेकर राय लेने का सवाल ही नहीं है। जवाब केवल एक शब्द में है नहीं। बता दें कि सुरजेवाला ने मामले में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। इस दौरान सुरजेवाला के साथ कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और राय के डिप्टी सीएम डीके. शिवकुमार भी मौजूद थे। सुरजेवाला ने बताया कि वे विधायकों, सांसदों, एमएलसी और हाल में विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़े उम्मीदवारों से मुलाकात

कर रहे हैं। सुरजेवाला ने कहा कि हम अपने विधायकों से मिल रहे हैं ताकि जान सकें कि उन्होंने बीते दो वर्षों में अपने क्षेत्र में क्या काम किया है। हर विधायक की जनता के प्रति जवाबदेही होती है और कांग्रेस के चुनावी वादों को पूरा करना उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए हम उनसे रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं। सुरजेवाला ने आगे कहा कि विधायकों से यह भी पूछा जा रहा है कि उनके क्षेत्र में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और विधानसभा कांग्रेस कमेटी की क्या स्थिति है और उन्होंने कितनी बार पार्टी बैठकें आयोजित कीं। साथ ही, उनसे यह भी पूछा जा रहा है कि उन्हें अपने क्षेत्र में किन दिक्कतों या जरूरतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि विधायकों की कोई अपेक्षाएं हैं तो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सरकार तक पहुंचाया जाएगा। विधायकों के बाद, सुरजेवाला ने बताया कि वे मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे ताकि यह जाना जा सके कि उन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में क्या कार्य किया है। इसके साथ ही युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एससी/एसटी, ओबीसी, किसान और अल्पसंख्यक विभाग जैसे फ्रंटल संगठनों की भूमिका की भी समीक्षा की जाएगी। सुरजेवाला ने कहा कि इस दौरान सरकार की पांच बड़ी गारंटी योजनाओं की भी समीक्षा की जाएगी। गौरतलब है कि कर्नाटक कांग्रेस की पांच प्रमुख योजनाओं में महिलाओं को 3,000 मासिक सहायता देना, किसानों के लिए 3 लाख तक का कर्ज माफी, हर परिवार को 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा देना, बेरोजगार युवाओं को 4,000 मासिक भत्ता देना और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जैसी योजनाएं शामिल है। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने आगे भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह इन योजनाओं को बंद कराना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा चाहती है कि 58,000 करोड़ रुपये कन्नड़ जनता के खातों में न जाएं। लेकिन कांग्रेस की गारंटी योजनाएं कभी बंद नहीं होंगी। इसके अलावा अंत में सुरजेवाला ने उन विधायकों को भी सलाह दी जो सार्वजनिक रूप से सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी विधायक को कोई समस्या है तो उसे परिवार के मुखिया से बात करनी चाहिए पार्टी के लिए डी.के. शिवकुमार और सरकार के लिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर की बातों को सार्वजनिक मंच पर लाना उचित नहीं है।

भारत-पाक ने एक-दूसरे की जेलों में बंद अपने नागरिकों की सूची का किया आदान-प्रदान, सरकार ने दी जानकारी

नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान ने मंगलवार एक-दूसरे की जेलों में बंद नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान-प्रदान किया। नई दिल्ली और इस्लामाबाद में यह आदान-प्रदान राजनयिक माध्यमों से एक साथ किया गया। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी। विदेश मंत्रालय ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि यह प्रक्रिया साल 2008 के द्विपक्षीय कांसुलर एक्सेस समझौते के तहत होती है। इस समझौते के अनुसार, हर साल एक जनवरी और एक जुलाई को ऐसी सूचियों का आदान-प्रदान किया जाता है। विज्ञप्ति के मुताबिक, भारत ने पाकिस्तान को अपने पास मौजूद 382 नागरिक कैदियों और 81 मछुआरों के नामों की सूची दी, जो पाकिस्तानी हैं या जिन्हें पाकिस्तानी माना जाता है। वहीं, पाकिस्तान ने भारत को 53 नागरिक कैदियों और 193 मछुआरों के नामों की सूची दी, जो भारतीय हैं या जिन्हें भारतीय माना जाता है। भारत सरकार ने पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वह भारतीय नागरिक कैदियों, मछुआरों और उनके साथ पकड़ी गई नावों को जल्द रिहा करके भारत भेजे। इसके अलावा, भारत ने पाकिस्तान से मांग की है कि वह 159 भारतीय मछुआरों और नागरिक कैदियों की जल्द रिहाई करे, जिनकी सजा पूरी हो चुकी है। साथ ही, पाकिस्तान की हिरासत में मौजूद 26 भारतीय माने जा रहे कैदियों और मछुआरों को अब तक कांउसुलर एक्सेस नहीं मिला है- भारत ने उनके लिए भी तुरंत संपर्क की अनुमति मांगी है। भारत ने यह भी कहा है कि उनकी रिहाई तक पाकिस्तान को उनकी सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करनी चाहिए। भारत सरकार ने कहा कि वह मानवीय मामलों को प्राथमिकता के साथ हल करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें एक-दूसरे के देश में बंद कैदी और मछुआरे भी शामिल हैं। इसी क्रम में, भारत ने पाकिस्तान से अपील की है कि वह 80 ऐसे लोगों की नागरिकता की पुष्टि जल्द करे, जिन्हें भारत ने पाकिस्तानी माना है और जिनकी वापसी इस पुष्टि के अभाव में रुकी हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा, सरकार के निरंतर प्रयासों का नतीजा है कि 2014 से अब तक पाकिस्तान से 2,661 भारतीय मछुआरों और 71 भारतीय नागरिक कैदियों को भारत वापस लाया गया है। इसमें 2023 से अब तक 500 मछुआरे और 13 नागरिक कैदी भी शामिल है।

प्रियदर्शिनी मट्टू हत्याकांड : समय पूर्व रिहाई की याचिका पर हुई सुनवाई, अदालत ने कहा-सजा बोर्ड फिर से विचार करे

नई दिल्ली। प्रियदर्शिनी मट्टू मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दोषी की समयपूर्व रिहाई की याचिका खारिज करने का फैसला रद्द किया।

साथ ही कोर्ट ने सजा बोर्ड से फिर से विचार करने को कहा है। संतोष कुमार सिंह 1996 में कानून की छात्रा प्रियदर्शिनी मट्टू से दुष्कर्म और हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। जस्टिस संजीव नरूला ने 14 मई को सिंह की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा था। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने कहा कि सिंह में सुधार की भावना है और उन्होंने दोषी की समयपूर्व रिहाई की याचिका पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामले को सजा समीक्षा बोर्ड (एसआरबी) के पास वापस भेज दिया। न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुझे उसमें सुधार की भावना मिली है। एसआरबी के फैसले को खारिज किया जाता है और मैंने मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए एसआरबी के पास वापस भेज दिया है। न्यायालय ने कैदियों की याचिकाओं पर विचार करते समय एसआरबी द्वारा पालन किए जाने वाले कुछ दिशा-निर्देश भी तैयार किए हैं। न्यायालय ने कहा कि एसआरबी को दोषियों की याचिकाओं पर विचार करते समय उनका मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करना चाहिए, जो इस मामले में नहीं किया गया। माथुर ने कहा था कि उनके मुवक्किल का आचरण संतोषजनक रहा है, जो उनके सुधार का संकेत देता है और भविष्य में अपराध करने की उनकी संभावना पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि सिंह कई वर्षों से ओपन जेल में हैं और समाज के लिए एक उपयोगी सदस्य बन सकते हैं।

समाजवादी नहीं, असल में नमाजवादी हैं तेजस्वी, भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राजद नेता पर बोला करारा हमला

नई दिल्ली । बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने है। इसको लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी-अपनी तैयारी भी तेज कर चुकी है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी खुद को समाजवादी कहते हैं, असल में वे नमाजवादी हैं। भाटिया ने आरोप लगाया कि ये लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान को नहीं मानते, बल्कि शरीयत कानून लागू करना चाहते हैं। भाजपा नेता ने आगे पूरे इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग सिर्फ एक समुदाय को ताकत देना चाहते हैं, न कि पिछड़े वर्गों, दलितों और महिलाओं को जैसा प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं। भाटिया ने कहा कि भाजपा संविधान की बात करेगी, ये लोग शरीयत की। फैसला जनता को करना है कि वो किसके साथ है। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि वो संसद से पास हुए वक्फ संशोधन बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे। गौरव भाटिया ने आगे तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या किसी राज्य की सरकार संसद और राष्ट्रपति द्वारा पास किए गए कानून को खारिज कर सकती है? क्या तेजस्वी

संविधान से ऊपर हो गए हैं? साथ ही भाटिया ने तेजस्वी को मौलाना तेजस्वी यादव बताते हुए कहा कि वे केवल तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं और खुद कभी संविधान को पढ़ा भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यह मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और अदालत ने अभी फैसला सुरक्षित रखा है। ऐसे में तेजस्वी कैसे कह सकते हैं कि कानून असंवैधानिक है? इसके साथ ही तेजस्वी की तरफ से 20 महीने का समय मांगे जाने पर गौरव भाटिया ने कहा कि बिहार की जनता ने यादव परिवार को 10 साल से ज्यादा का वक्त दिया, लेकिन क्या मिला? कानून-व्यवस्था तबाह हो गई, जनता परेशान रही। आज ये लोग युवाओं की बात करते हैं, जबकि अब तक अपनी पार्टी में कोई भी पद या मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने परिवार से बाहर नहीं दी। उन्होंने तेजस्वी यादव पर वंशवाद, अराजकता और जंगलराज को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि बिहार को फिर से उसी अंधेरे में ले जाया जा रहा है, जहां कभी लालू यादव शासन हुआ करता था। गौरतलब है कि सोमवार को वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ इंडिया गठबंधन के नेता पटना के गांधी मैदान एक जुट हुए थे। इस दौरा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि उत्तर से दक्षिण हिन्दुस्तान का एक-एक इंच और हर पन्ना चीख-चीख कर कह रहा है कि हिन्दू, मुसलमान समेत सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया था। सबलोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी। यह देश किसी के बाप का नहीं है। यह हमलोगों का देश है। लेकिन, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सभी का हक छीना जा रहा है। अब भाजपा सत्ता से जा रही है। इसलिए गरीब, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और अल्पसंख्यकों का हक छीनना चाहती है।

रहेजा बिल्डर के खिलाफ ईडी का एक्शन, संपत्ति जब्त; दिल्ली-एनसीआर में 13 ठिकानों पर मारा था छापा

नई दिल्ली । बीती 27 जून को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दिल्ली, एनसीआर और मोहाली में 13 स्थानों पर छापा मारा। जिसके बारे में ईडी ने जानकारी साझा की है। ईडी ने कहा कि दिल्ली जोनल कार्यालय ने 27 जून को दिल्ली, एनसीआर और मोहाली में 13 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत रहेजा डेवलपर्स के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने रहेजा डेवलपर्स, इसके प्रबंध निदेशक, नवीन रहेजा और अन्य के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और चल-अचल संपत्तियों की जानकारी मिली। जिन्हें जब्त किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक कदम, पहली बार स्टाफ के लिए आरक्षण नीति लागू

नई दिल्ली ।सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 75 साल के इतिहास में पहली बार स्टाफ के लिए आरक्षण नीति लागू की है। इसके तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट के गैर न्यायिक पदों पर नियुक्तियों और प्रमोशन में आरक्षण का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण नीति 23 जून 2025 को लागू हुई। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रशासनिक कामकाज में बड़े बदलाव का संकेत है। हालांकि जजों पर आरक्षण लागू नहीं होगा और सिर्फ रजिस्ट्रार, वरिष्ठ निजी सहायक, सहायक लाइब्रेरियन, जूनियर कोर्ट सहायक, चैंबर अटेंडेंट आदि पदों पर आरक्षण लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के तहत तीन कैटेगरी होंगी, जिनमें एससी, एसटी और गैर आरक्षित शामिल होंगी। आरक्षण लागू करने को लेकर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि अगर सभी सरकारी संस्थानों और विभिन्न उच्च न्यायालयों में आरक्षण नीति लागू है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को ही क्यों अपवाद रखा जाए? उन्होंने कहा कि हमारे मूल्य हमारे एक्शन का आईना होना चाहिए। 24 जून को जारी सर्कुलर के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में अनुसूचित जाति (एससी) के कर्मचारियों को 15 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, जबकि अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग को 7.5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

एम्स के शोध में खुलासा : चिड़चिड़ापन और तनाव पड़ रहा बुढ़ापे पर भारी, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलतियां

नई दिल्ली । जवानी में चिड़चिड़ापन, छोटी-छोटी बातों से तनाव होना बुढ़ापे पर भारी पड़ रहा है। इसका खुलासा एम्स के विशेषज्ञ के शोध में हुआ है। इसमें 100 मरीजों पर अध्ययन किया गया। उसमें पाया गया कि जो लोग छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा होने की बजाय खुश रहते हैं उनकी 75 साल की उम्र के बाद भी अच्छी याददाश्त रहती है। उनके चेहरे पर खुशी व मस्तिष्क के काम करने का स्तर बेहतर रहता है। यह शोध जर्नल ऑफ द इंडियन एकेडमी ऑफ जेरियाट्रिक्स में प्रकाशित हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि 25 से 50 साल की उम्र में छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा होना, तनाव लेना, चिड़चिड़ापन रहना मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं। एम्स के पूर्व प्रोफेसर व जेरियाट्रिशियन डॉ. प्रसून चटर्जी ने बताया कि यह अध्ययन एशिया में पहला शोध है। इसमें यह जांच की गई है कि व्यक्तित्व लक्षण सुपरएजिंग का समर्थन कैसे कर सकते हैं। यह अध्ययन बताता है कि कैसे व्यक्तित्व को बुढ़ापे में बेहतर रख सकते हैं। शोध के मुताबिक न्यूरोटिसिज्म के उच्च स्तर वाले व्यक्ति अधिक तनाव का अनुभव करते हैं। उनके संज्ञानात्मक प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। साथ ही अवसाद के लक्षणों को बढ़ाता है। यह उम्र बढ़ने वाली आबादी में संज्ञानात्मक लचीलेपन से जुड़े जटिल कारकों की समस्या को बढ़ाता है। 100 मरीजों को तीन ग्रुपों में बांटा गया। पहले ग्रुप में 75 साल से अधिक उम्र (सुपरएजिंग) के करीब 40 वह लोग थे जिनकी याददाश्त व दूसरे व्यवहार 50 साल के लोगों की तरह थे। दूसरे ग्रुप में 75 साल के करीब 30 वह लोग थे जो सामान्य व्यवहार कर रहे थे। वहीं तीसरे ग्रुप में 25 से 50 साल के करीब 30 लोग शामिल थे। शोध में तीनों ग्रुप का ब्रेन फंक्शन का अध्ययन किया गया। भारत में बुजुर्ग लोगों की संख्या आने वाले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि मौजूदा 25 से 50 साल के लोग तनाव लेंगे। छोटी-छोटी बातों पर खुद का नियंत्रण खो देंगे तो आने वाले समय में बुजुर्ग में समस्या ज्यादा बढ़ेगी।

कन्वर्जन शुल्क न रोका जा सकता न ही सीलिंग, एमसीडी आयुक्त की रिपोर्ट ने बताई एमसीडी की सीमाएं

नई दिल्ली ।एमसीडी आयुक्त की हालिया रिपोर्ट ने कन्वर्जन प्रभार, पार्किंग शुल्क और दुकानों की सीलिंग से जुड़ी कार्रवाई पर अपनी सीमाएं बताई। उन्होंने रिपोर्ट में साफ कहा कि एमसीडी के पास इन प्रभारों को हटाने या कार्रवाई पर रोक लगाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यह पूरी व्यवस्था दिल्ली विकास प्राधिकरण के माध्यम से केंद्र सरकार की मंजूरी से अधिसूचित मास्टर प्लान दिल्ली-2021 के अधीन संचालित होती है। एमसीडी महज अनुपालक संस्था है। आयुक्त ने स्थायी समिति के समक्ष यह रिपोर्ट तीन प्रस्तावों के जवाब में पेश की है। यह प्रस्ताव वर्ष 2023 में आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने पारित करवाए थे। इन प्रस्तावों में व्यापारियों को राहत देने के नाम पर नोटिस भेजने और सीलिंग की कार्रवाइयों पर तत्काल रोक की मांग की गई थी। रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया कि कन्वर्जन और पार्किंग प्रभारों की दरें और शर्तें केवल डीडीए और केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय तय करता है। एमसीडी को इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। मास्टर प्लान के प्रावधानों में कोई भी छेड़छाड़ केवल केंद्र सरकार की अधिसूचना के माध्यम से ही संभव है। मार्च 2023 में आम आदमी पार्टी के पार्षद रविन्द्र भारद्वाज, प्रेम चौहान और मुकेश गोयल ने तीन प्रस्ताव एमसीडी सदन में बजट पास करने के दौरान पास कराए थे। इन प्रस्तावों में यह मांग थी कि जब तक पारदर्शी नीति न बन जाए, तब तक कन्वर्जन शुल्क और सीलिंग नोटिसों पर रोक लगाई जाए। उस समय सत्तारूढ़ आप ने इसे व्यापारियों और छोटे व्यावसायियों के हित में बड़ा कदम बताया था, लेकिन अब आयुक्त की रिपोर्ट ने उन प्रस्तावों की व्यवहारिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष और आप के वरिष्ठ पार्षद अंकुश नारंग ने आयुक्त के रुख पर दोहरे तौर पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि एक ओर आयुक्त ने सवा दो साल बाद रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह प्रस्ताव सदन में पास हुए थे तो वे सदन में अपनी रिपोर्ट बहुत पहले प्रस्तुत कर सकते थे, वहीं दूसरी ओर प्रस्ताव एमसीडी के लिए अपने स्तर पर लागू करना असंभव है और इन प्रस्तावों को लागू करने की प्रक्रिया डीडीए को पूरी करनी है तो आयुक्त को यह प्रस्ताव डीडीए के पास भेजने चाहिए थे।

बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण से बेचैन हुआ विपक्ष

डॉ. आशीष वशिष्ठ ।

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन –एस.आई.आर.) का काम शुरू हो गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक उसकी इस पहल का मकसद मतदाता सूची को शुद्ध और वास्तविक बनाना है। हालांकि, विपक्षी दलों ने मतदाता सूची में छेड़छाड़ के व्यापक आरोप लगाए हैं। लगभग सभी ने एसआईआर का विरोध किया है और कहा है कि इससे मताधिकार से वंचित होने का गंभीर खतरा है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर 7.89 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। राज्य में इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार में इस तरह का आखिरी गहन संशोधन 2003 में किया गया था। चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार में 2003 की मतदाता सूची को फिर से वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, जिसमें 4.96 करोड़ लोगों के नाम हैं। इनमें शामिल लोगों को जन्मतिथि या जन्मस्थान साबित करने के लिए दस्तावेज नहीं देने होंगे। बाकी 3 करोड़ मतदाताओं को प्रमाण के लिए दस्तावेज देने होंगे। वोटिंग लिस्ट में ये संशोधन ऐसे वक्त किए जाने हैं जब बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में विपक्षी पार्टियां इस पर नाराजगी जता रही हैं। इस मसले पर विपक्ष की ओर से एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कई मुद्दे उठाए थे और व्यावहारिक समस्याएं बताई थीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस कदम को एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर) से भी ज्यादा खतरनाक बताया और आरोप लगाया कि उनका राज्य, जहां अगले साल चुनाव होने हैं, असली लक्ष्य है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 7 जून को महाराष्ट्र की मैच फिक्सिंग के बारे में कई बातें लिखी थीं। उन्होंने लिखा था, क्योंकि महाराष्ट्र की यह मैच फिक्सिंग अब बिहार में भी दोहराई जाएगी और फिर वहां भी, जहां-जहां बीजेपी हार रही होगी। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने 28 जून को कहा कि चुनाव आयोग द्वारा घोषित मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण 'पिछले दरवाजे से एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) लाने का एक भयावह कदम' है। इससे पहले ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर सवाल उठाए। उन्होंने 27 जून को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, निर्वाचन आयोग बिहार में गुप्त तरीके से एनआरसी लागू कर रहा है। जबकि सत्तारूढ़ दलों ने इसी पूर्व की चुनावी धांधली पर चुनाव आयोग की सख्ती के साथ पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। महागठबंधन के प्रमुख घटक दल राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2003 में जब मतदाता सूची का पुनरीक्षण हुआ था तो उसमें दो साल लगे थे और तब साढ़े चार करोड़ से कुछ ज्यादा मतदाता थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) का मानना है कि विधानसभा चुनाव से एक महीने पहले सघन पुनरीक्षण अभियान संभव नहीं है। राजद नेताओं ने सवाल उठाया कि अगर मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की इतनी आवश्यकता है, तो यह केवल बिहार में ही क्यों किया जा रहा है? क्या देश के अन्य राज्यों को इसकी जरूरत नहीं है? नेताओं ने आरोप लगाया कि यह पूरी प्रक्रिया बिहार को निशाना बनाने की एक सोची-समझी रणनीति है। संविधान का अनुच्छेद 324 (1) भारत के निर्वाचन आयोग को संसद और राज्य विधानसभा चुनाव के- चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और उनके संचालन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति देता है। गहन पुनरीक्षण में मतदाता सूची को नए सिरे से तैयार किया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग बिहार के बाद, चुनाव आयोग इस वर्ष के अंत तक 2026 में चुनाव होने वाले पांच राज्यों में मतदाता सूचियों की इसी प्रकार की समीक्षा करेगा। असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं का कार्यकाल अगले वर्ष मई-जून में समाप्त हो रहा है। ध्यान रहे पश्चिम बंगाल और असम दोनों ही राज्यों में एनआरसी बड़ा मुद्दा है क्योंकि इन राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठियों और शरणार्थियों की बड़ी संख्या है। राजनीतिक हलकों में इस बात की जोरों से चर्चा है कि बिहार के बाद मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की बारी पश्चिम बंगाल की होगी। तभी पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस बहुत बेचैन है। तृणमूल कांग्रेस को यह चिंता सता रही है कि अगर चुनाव आयोग ने चुनिंदा विधानसभा क्षेत्रों में टारगेट करके मतदाताओं के नाम काटे तो उसका फायदा भाजपा को होगा। पश्चिम बंगाल में 30 फीसदी मुस्लिम आबादी है, जिसके बारे में भाजपा आरोप लगाती है कि इनमें बड़ी संख्या बांग्लादेशी और रोहिंग्या की है। इनका वोट एकमुश्त तृणमूल को जाता है। हर क्षेत्र में 10 से 20 हजार नाम अगर कट जाते हैं तो तृणमूल को उसका बड़ा नुकसान होगा। हालांकि बिहार से उलट पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता ज्यादा जागरूक और सक्रिय हैं। वे आसानी से नाम नहीं कटने देंगे। पिछले कई महीनों से वे खुद घर घर जाकर सब चेक कर रहे हैं। बिहार की राजनीति को करीब से जानने वालों के अनुसार, निर्वाचन आयोग देश में अवैध रूप से बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार से आकर जो लोग रह रहे हैं, जिन्होंने मतदाता सूची में नाम दर्ज करवा लिया है। वैसे लोगों को मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू की है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी अवैध रूप से बिहार आकर बस गए हैं, उनका वोट विपक्ष को जाता है। यही कारण है कि इंडिया गठबंधन के घटक दल हो या ओवैसी, इनको इस बात का डर सता रहा है कि मतदाता सूची से यदि इनका नाम कट गया तो उनका राजनीतिक रूप से नुकसान होगा। बिहार के सीमांचल के इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला वर्षों से सामने आ रहा है। पिछले 30 वर्षों में पूरे सीमांचल का समीकरण बदल गया है। किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया में अल्पसंख्यकों की आबादी 40 फीसदी से 70 फीसदी तक हो चुकी है। यही कारण है कि वर्षों से इस इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठियों की रोक की मांग उठती रही है। कई इलाकों से हिंदुओं के पलायन की भी खबर उठी थी। केंद्र सरकार ने जब पूरे देश में एनआरसी लागू करने की बात कही थी तो बिहार में इस इलाके से भी विरोध के सुर उठे थे। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजद का वोट शेयर बढ़ा था। राजद को 23.11 फीसदी वोट मिले। भाजपा को 19.46 प्रतिशत ही वोट मिले, जदयू के खाते में 15.42 प्रतिशत वोट आया। 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार में भाजपा और जेडीयू ने 12-12 सीटें जीतीं। आरजेडी ने 4 सीटें, कांग्रेस ने 3 सीटें और एलजेपी (आर) ने 5 सीटें जीती हैं। सीपीआई (एमएल) ने 2 सीटें जीती हैं, जबकि एचएएम और एक स्वतंत्र उम्मीदवार ने 1-1 सीट जीती है। जाति आधारित सर्वेक्षण आंकड़ों के अनुसार बिहार में करीब 17.70 फीसदी मुस्लिम मतदाता हैं। वहीं, बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें ऐसी हैं, जहां मुस्लिम वोटर अहम भूमिका अदा करते हैं। इन इलाकों में मुस्लिम आबादी 20 से 40 प्रतिशत या इससे भी अधिक है। बिहार की 11 सीटें हैं, 10 से 30 फीसदी के बीच मुस्लिम मतदाता हैं। जानकारों का मानना है कि चुनिंदा क्षेत्रों में अगर एक निश्चित मात्रा में नाम कट जाएं तो मुकाबला कमजोर हो जाएगा।

हम एक उंगली दूसरे पर उठाते हैं तो तीन उंगलियां हमारे ऊपर उठती है इस को रेखांकित करना ज़रूरी

सृष्टि में खूबसूरत मानवीय जीव की रचना कर रचनाकर्ता ने उसमें गुण और अवगुण रूपी दो गुलदस्ते भी जोड़े है और उनका चयन करने के लिए 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ बुद्धि का सृजन मानवीय योनि में कर अपने भले बुरे सोचने का हक उसी को दिया है,परंतु हम अपनी जीवन यात्रा में देखते हैं कि मानवीय जीव अवगुण रूपी गुलदस्ते का चुनाव खुद कर उसमें ढल जाता है और अंत में दोष सृष्टि रचनाकर्ता को ही देता है कि मेरे जीवन को नरक बना दिया जबकि गलती मानवीय जीव की ही है कि उसने ही अपनी बुद्धि से उस अवगुण रूपी गुलदस्ते को चुना! मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि कहावत जब हम एक उंगली उठाते हैं, तो तीन उंगलियां हमारी ओर इशारा करती हैं अक्सर आत्म-चिंतन और जवाबदेही के विचार से जुड़ी होती है। यह वाक्यांश बताता है कि जब हम किसी और पर आरोप लगाते हैं या दोष देते हैं,तो हमको उस स्थिति में अपनी गलतियों या योगदानों पर भी विचार करना चाहिए।हालांकि इस कहावत की सटीक उत्पत्ति स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह विभिन्न सांस्कृतिक और दार्शनिक परंपराओं में पाए जाने वाले विषयों को समाहित करती है। यह प्रक्षेपण के बारे में मनोविज्ञान की अवधारणाओं के साथ संरेखित है, जहां व्यक्ति अपने अवांछनीय गुणों या व्यवहारों को दूसरों पर आरोपित करते हैं। उंगलियों की छवि यह दर्शाती है कि आलोचना अक्सर आलोचना के विषय की तुलना में आलोचक के बारे में अधिक दर्शाती है। इस वाक्यांश की खूबसूरती यह है कि यह किसी और को दोष देने के बजाय आत्मनिरीक्षण करने पर मजबूर करता है।यूं तो अवगुणों को सैकड़ों शब्दों, बुराइयों से पुकारा जाता है जिसमें आज हम निंदा बुराई, दूसरों पर उंगली उठाना इस अवगुण की चर्चा कर करेंगे आओ निंदा रूपी अवगुण त्यागने का संकल्प लें। हम खुद का आकलन दूसरे से श्रेष्ठ करने की चूक से बचें स्वयं को छोटा कहलाने वाला व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ गुणवान होता है। साथियों बात अगर हम निंदा की करें तो किसी ने खूब ही कहा है कि, संसार में प्रत्येक जीव की रचना ईश्वर अल्लाह ने किसी उद्देश्य से की है। हमें ईश्वर अल्लाह की किसी भी रचना का मखौल उड़ाने का अधिकार नहीं है। इसलिए किसी की निंदा करना साक्षात परमात्मा की निंदा करने के समान है।किसी की आलोचना से आप खुद के अहंकार को कुछ समय के लिए तो संतुष्ट कर सकते हैं किन्तु किसी की काबिलियत, नेकी, अच्छाई और सच्चाई की संपदा को नष्ट नहीं कर सकते। जो सूर्य की तरह प्रखर है, उस पर निंदा के कितने ही काले बादल छा जाएं किन्तु उसकी प्रखरता, तेजस्विता और ऊष्णता में कमी नहीं आ सकती। साथियों बात अगर हम खुद का आंकलन दूसरों से सर्वश्रेष्ठ करने की करें तो, अपनी प्रशंसा तथा दूसरों की निंदा असत्य के समान है। जैसे हमारी आंखें चंद्रमा के कलंक तो देख लेती हैं , किंतु अपने काजल को नहीं देख पातीं। उसी प्रकार हम दूसरों के दोषों को देखते हैं , हालांकि खुद अनेक दोषों से भरे हैं।

दूसरों में जो दोष दिखाई देते हैं , सचमुच उनका कारण हमारे अपने चित्त की दूषित वृत्तियां ही है। दूसरों की निंदा किसी भी दृष्टि से हितकर नहीं होती। इस संबंध में एक कवि ने लिखा भी है कि हमें परखने का तरीका नहीं है। कोई वरना दुश्मन किसी का नहीं है। निंदक को यह याद रखना चाहिए कि दुनिया तुझे हजारों आंखों से देखेगी , जबकि तू दुनिया को दो ही आंखों से देख सकेगा। साथियों बात अगर हम दूसरों पर एक उंगली उठाने की करें तो, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के दोषों पर उंगली उठाता है , तो उसे याद रखना चाहिए कि पीछे की ओर मुड़ी उसकी तीन उंगलियां पहले उसी की ओर संकेत कर रही होती हैं। निंदा- चुगली व्यर्थ ही है। इससे परस्पर वैमनस्य , कटुता और संघर्ष बढ़ते हैं। इसीलिए कहा है कि दूसरों के कृत्याकृत्यों को न देखो , केवल अपने ही कृत्यों का अवलोकन करो। यूं तो लोग चुप रहने वाले की निंदा करते हैं। बहुत बोलने वाले की निंदा करते हैं ,मातृ भाषी की निंदा करते है , संसार में ऐसा कोई नहीं है , जिसकी निंदा न होती हो, इसीलिए कहा है- जैसी जाकी बुद्धि है , तैसी कहै बनाय। ताको बुरा न मानिए , लेन कहां यूं जाए। केवल दूसरों द्वारा अपनी निंदा सुनकर मनुष्य अपने को निंदित न समझें , वह अपने आप को स्वयं ही जाने , क्योंकि लोक तो निरंकुश है , जो चाहता है सो कह देता है। द्वेषी गुण न पश्यति , दोषी गुणों को नहीं देखता। साथियों बात अगर हम पर निंदा में आनंद की करेंतो परनिंदा में प्रारंभ में काफी आनंद मिलता है लेकिन बाद में निंदा करने से मन में अशांति व्याप्त होती है और हम हमारा जीवन दुःखों से भर लेते हैं। प्रत्येक मनुष्य का अपना अलग दृष्टिकोण एवं स्वभाव होता है। दूसरों के विषय में कोई अपनी कुछ भी धारणा बना सकता है। हर मनुष्य का अपनी जीभ पर अधिकार है और निंदा करने से किसी को रोकना संभव नहीं है। न बिना परवादेन रमते दुर्जनोजन काक सर्वरसान भुक्ते विनामध्यम न तृप्यति।। अर्थ-लोगों की निंदा (बुराई) किये बिना दुष्ट (बुरे) व्यक्तियों को आनंद नहीं आता। जैसे कौवा सब रसों का भोग करता है परंतु गंदगी के बिना उसकी संतुष्टि नहीं होती, लोग अलग-अलग कारणों से निंदा रस का पान करते हैं। कुछ सिर्फ अपना समय काटने के लिए किसी की निंदा में लगे रहते हैं तो कुछ खुद को किसी से बेहतर साबित करने के लिए निंदा को अपना नित्य का नियम बना लेते हैं। निंदकों को संतुष्ट करना संभव नहीं है। साथियों बात अगर हम निंदा पर वैश्विक विचारों की करें तो, महात्मा गांधी ने भी कहा है कि दूसरों के दोष देखने की बजाय हम उनके गुणों को ग्रहण करें। दूसरों की निंदा अश्रेयस्कारी है।

निंदा करने व सुनने में व्यक्ति प्राय आनंद लेता है। जबकि निंदा सुनना व निंदा करना, दोनों ही विषय है। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने तो कहा है सपनेहुं नहिं देखा परदोषा! अर्थात् स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। भगवान बुद्ध ने कहा है , जो दूसरों के अवगुणों की चर्चा करता है , वह अपने अवगुण प्रकट करता है। भगवान महावीर ने भी कहा है कि किसी की निंदा करना पीठ का मांस खाने के बराबर है। विधाता प्राय- सभी गुणों को किसी एक व्यक्ति या एक स्थान पर नहीं देता है। ईसा मसीह ने कहा था ,लोग दूसरों की आंखों का तिनका तो देखते है, पर अपनी आंख के शहतीर को नहीं देखते। हेनरी फोर्ड ने कहा कि मैं हमेशा दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करता हूं। हमारी सद्भावना या दुर्भावना ही किसी को मित्र या शत्रु मानने के लिए बाध्य करती है।सद्भावना अनुकूल स्थिति के कारण होती है और दुर्भावना प्रतिकूल स्थिति के कारण होती है। लोगों के छिपे हुए ऐब जाहिर मत करो। इससे उसकी इज्जत तो जरूर घट जाएगी, मगर तेरा तो ऐतबार ही उठ जाएगा। साथियों बात अगर हम दूसरों के दोष ढूंढना, निंदा करना मानवीय स्वभाव की करें तो, दूसरों की निंदा करना। सदैव दूसरों में दोष ढूंढते रहना मानवीय स्वभाव का एक बड़ा अवगुण है। दूसरों में दोष निकालना और खुद को श्रेष्ठ बताना कुछ लोगों का स्वभाव होता है। इस तरह के लोग हमें कहीं भी आसानी से मिल जाएंगे। प्रतिवाद में व्यर्थ समय गंवाने से बेहतर है अपने मनोबल को और भी अधिक बढ़ाकर जीवन में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहें। ऐसा करने से एक दिन आपकी स्थिति काफी मजबूत हो जाएगी और आपके निंदकों को सिवाय निराशा के कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसलिए सब तरफ गुण ही ढूंढने की आदत डालो। देखो कितना आनंद आता है। दुनिया में पूर्ण कौन है हरेक में कुछ न कुछ त्रुटियां रहती हैं। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर उसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि न बिना परवादेन रमते दुर्जनोजनन्न काकन्सर्वरसान भुक्ते विनामध्यम न तृप्यति।।आओ निंदा त्यागने का संकल्प लें हम एक उंगली दूसरों पर उठाते है तो तीन उंगलियां हमारे तरफ उठती है इसको रेखांकित करना जरूरी है हम खुद का आंकलन दूसरे से सर्वश्रेष्ठ करने की चूक से बचें, स्वयं का छोटा कहलानें वाले व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ गुणवान होतें है।

सम्पादकीय...

प्राकृतिक आपदा बाढ़ के प्रति राजनैतिक दलों का उदासीन रवैया

देश के कई राज्यों में भारी बारिश, बाढ़ और बादल फटने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भूस्खलन और बाढ़ से जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने जुलाई और अगस्त में और अधिक बारिश का अनुमान जताया है जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती है। भारी बारिश, बाढ़ और बादल फटने से लाखों लोग प्रभावित हैं। इन राज्यों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भारत में बाढ़ को सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक बताया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। इससे उनकी आजीविका भी प्रभावित होती है। प्राधिकरण के अनुसार, भारत में हर वर्ष आने वाली बाढ़ लगभग 75 लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्र को प्रभावित और करोड़ों रुपए का नुकसान करती है। बाढ़ जैसी आपदाओं से सड़कों, पुलों और सार्वजनिक उपयोगिताओं जैसे बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान होता है। इससे न केवल आर्थिक गतिविधियां बाधित होती हैं बल्कि यह लोगों की जिंदगी को भी प्रभावित करता है। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के अनुसार 1953 से 2017 के बीच भारत में बाढ़ से कुल 1,07,487 लोगों की मौत हुई है। इसमें 3,65,860 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, पर अब तक बाढ़ रोकने और नियंत्रित करने के लिए हम किसी कारगर योजना को अंजाम नहीं दे सके हैं। भारी जन और धन की क्षति होते हुए भी सरकार और राजनैतिक दल इस गंभीर प्राकृतिक आपदा और सामाजिक विपदा के प्रति उदासीन रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए लगातार प्रयास जरूर हो रहे हैं, इसके बावजूद यह सवाल फिर उठता है कि आखिर हर बार मानसून में भारी बारिश के बाद इतनी तबाही क्यों मचती है? हर साल हजारों की संख्या में जानें क्यों जाती हैं? सबसे अहम सवाल यह कि समय से पहले सरकारें लोगों को इससे राहत देने के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाती हैं? दुनिया भर के देश जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव न सिर्फ पर्यावरण पर हो रहा है, बल्कि इसका वास्तविक प्रभाव अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। यूरोपीय अकादमियों की विज्ञान सलाहकार परिषद् के अनुसार, 1980 के बाद दुनिया भर में बाढ़ की घटनाएं लगभग दोगुनी हो गई हैं। पर्यावरणविदों का मानना है कि बाढ़ का प्रमुख कारण पर्यावरण से छेड़छाड़ है। 2013 में उत्तराखंड की बाढ़ के समय भी पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों को नजरअंदाज कर लगातार हो रहे अनियोजित विकास कार्यों पर सवाल उठाए गए थे। यही स्थिति 2014 में श्रीनगर और 2015 की चेन्नई बाढ़ में भी देखने को मिली थी, जिसमें बिना सोचे-समझे हुए विकास कार्यों ने तबाही मचा दी थी। विशेषज्ञों के अनुसार नदियों, नालों के बहाव क्षेत्रों के आसपास अत्यधिक अवैध निर्माण और अतिक्रमण हो जाने से ये क्षेत्र सिकुड़ते जा रहे हैं। इसलिए अत्यधिक बारिश होने पर पानी का दबाव बढ़ जाता और आसपास के क्षेत्रों में जल प्रवाहित होने लगता है जिससे वहां जलभराव होने लगता है। कई शहरों की जल निकास प्रणालियां भी बेहतर नहीं हैं और अत्यधिक बारिश की स्थिति में उनकी क्षमता जवाब दे जाती है। कभी-कभी बांध या बैराज से पूर्व सूचना दिए बिना अचानक पानी छोड़ दिया जाता है जिससे नदी का जल स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है और उसके तट पर बसे शहरों में बाढ़ आ जाती है। कई शहर बहुत पुरानी जल निकासी व्यवस्था पर निर्भर हैं, जबकि उन शहरों की आबादी पहले से काफी बढ़ गई है और उनकी अवसंरचना भी बहुत परिवर्तित हो गई है। शहरों में बाढ़ का एक कारण अनियोजित शहरीकरण है। विशेषज्ञ कहते हैं कि बाढ़ को लेकर एक वैज्ञानिक ढंग से व्यापक स्टडी की जरूरत है। हर साल आने वाली बाढ़ सैकड़ों-हजारों लोगों की जान ले लेती है और पशुओं का जीवन भी संकट में पड़ जाता है। बाढ़ की स्थिति में लोगों के डूबने, संक्रमण फैलने, घायल होने और बिजली का करंट आदि लगने का खतरा बढ़ जाता है। बाढ़ आने पर शहरों की विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाती है साथ ही इमारतें, घर, परिवहन, संचार तथा अवसंरचना भी बुरी तरह प्रभावित होती हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भारत में बाढ़ को सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक बताया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। उन्हें बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इससे उनकी आजीविका भी प्रभावित होती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, भारत में हर वर्ष आने वाली बाढ़ लगभग 75 लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्र को प्रभावित और करोड़ों रुपए का नुकसान करती है। आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र के अनुसार 2020 में भारत में बाढ़ की वजह से लगभग 54 लाख लोगों का विस्थापन हुआ था। इस साल की बाढ़ ने भी हजारों लोगों को स्थापित होने पर मजबूर कर दिया है। भारत में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान में तेजी से वृद्धि हुई है। 2013-2022 के दशक में हर साल औसतन 8 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 66,000 करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ। यह 2003-2012 के दशक की तुलना में 125 फीसदी अधिक है, जब यह आंकड़ा 3.8 अरब डॉलर था। वर्ष 2024 के नुकसान की गणना अभी बाकी है जो इतिहास में भारत का सबसे गर्म साल रहा है। यह वृद्धि बताती है कि या तो प्राकृतिक आपदाएं अधिक बार आ रही हैं, अधिक गंभीर हो गई है या दोनों ही बातें हो रही हैं। देश में बाढ़ से तबाही की कहानी हर साल एक ही तरह है। हर साल भारी बारिश से कई राज्य (देश का करीब 15 फीसदी हिस्सा) प्रभावित होते हैं। कई जिले और गांव डूब जाते हैं। लाखों लोग प्रभावित होते हैं। सरकारें राहत कैंप आयोजित करती है, मुआवजा देती है और फिर अगले साल वही कहानी। तबाही का क्रम वही है लेकिन आपदा प्रबंधन में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है, इसीलिए स्थितियां जस की तस बनी रहती हैं। करीब 1800 करोड़ रुपये कीमत की फसलें बर्बाद होती हैं। अब तक बाढ़ रोकने के जितने उपाय किए गए है उनसे यह समस्या और जटिल हो गई है। आधे-अधूरे संकल्पों और न्यस्त स्वार्थों के कारण हम बाढ़ों के विस्तार को रोकने में तो असफल रहे हैं, बल्कि बाढ़ से होने वाली क्षति को भी कम करने में विफल रहे हैं। नदियों को जोड़ने की परियोजना भी जमीन पर नहीं उतर पाई। वहीं शहरी अवसंरचना पर विशेष ध्यान देने की भी जरूरत है।

मुस्लिम वक्फ बोर्ड और बिहार

नये मुस्लिम वक्फ बोर्ड कानून को लेकर जिस प्रकार की राजनीति हो रही है वह देश के हित में नहीं है। यह कानून इसी वर्ष मोदी सरकार ने संसद में विधेयक पारित करा कर बनाया था। इसके विरोध में बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में कल एक रैली का आयोजन किया गया। यह रैली 'इमारते शरीया' मुस्लिम संगठन की ओर से आयोजित की गई थी। इसका समर्थन प्रमुख विपक्षी दलों ने प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से किया। भारत में रक्षा मन्त्रालय व रेलवे के बाद सर्वाधिक जमीन लगभग नौ लाख एकड़ बोर्ड के पास है। सवाल यह है कि इतनी बड़ी सम्पत्ति व जायदाद को संभालने के लिए क्या धर्मनिरपेक्ष भारत में किसी एक ही धर्म के मानने वाले लोगों को अधिकृत किया जा सकता है? सरकार ने नये कानून में ऐसे प्रावधान किये हैं जिससे वक्फ बोर्ड के प्रशासन में गैर मुस्लिम पदेन व्यक्तियों को भी रखा जा सके। जैसे यदि किसी जिले का जिलाधीश गैर मुस्लिम है तो वह जिले में वक्फ की सम्पत्तियों की देखभाल के लिए बोर्ड में नियुक्त किये गये लोगों का मुखिया होगा। इसमें किसी भी मुस्लिम नागरिक को क्या आपत्ति हो सकती है। मगर कल पटना की रैली में विभिन्न वक्ताओं द्वारा जो उद्गार व्यक्त किये गये उन्हें भारत की एकता के हित में नहीं कहा जा सकता। मगर इससे भी ऊपर सबसे बड़ा सवाल यह है कि 1947 में जब भारत के दो टुकड़े केवल मजहब के आधार पर ही किये गये तो वह जमीन किसकी थी? पूरे पाकिस्तान की जमीन भी तो तब भारत व भारतीयों की थी। अतः पाकिस्तान बनाने वाले मुहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान किस आधार पर बनाया? इस सिलसिले में यह ऐतिहासिक तथ्य है कि 40 के दशक में जब जिन्ना की मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग से पाकिस्तान बनाने की मुहीम छेड़ी तो यह प्रस्ताव आया कि इस मुद्दे पर जनमत संग्रह या रायशुमारी कराई जाये। महात्मा गांधी इसके लिए राजी थे मगर उनकी यह शर्त थी कि रायशुमारी में सभी हिन्दू-मुसलमान शामिल किये जाने चाहिए। मगर जिन्ना चाहते थे कि रायशुमारी केवल मुस्लिम नागरिकों के बीच ही हो। इस पर महात्मा गांधी किसी सूरत में भी राजी नहीं थे। अतः रायशुमारी का विकल्प समाप्त हो गया और अंग्रेजों ने जिन्ना के साथ साजिश करके पाकिस्तान का निर्माण मुस्लिम बहुल राज्यों पंजाब व बंगाल का बंटवारा करके करा दिया। मुस्लिम वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम में ऐसा क्या है जिसे विपक्षी दलों के गठबन्धन इंडिया का समर्थन मिल रहा है। धर्मनिरपेक्षता कभी भी इकतरफा नहीं हो सकती। 1954 में पहले प्रधानमन्त्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने बोर्ड का गठन किया और बीच-बीच में इसमें संशोधन होते रहे मगर पीवी नरसिम्हा राव के शासन काल के दौरान इसमें जो संशोधन किया गया उससे वक्फ बोर्ड के पास यह अधिकार आ गया कि वह जिस जमीन को चाहे वक्फ की जमीन घोषित कर सकता है। नरसिम्हा राव ने इस कानून में तब संशोधन किया था जब 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया था।

अपने प्रति मुसलमानों की सहानुभूति बटोरने के उद्देश्य से यह कार्य किया गया था। मैं इसके तकनीकी कानूनी पहलुओं पर नहीं जा रहा हूं मगर इतना कहना चाहता हूं कि यह कानून इकतरफा हो गया था। बाद में इसी कानून में कुछ संशोधन डा. मनमोहन सिंह की दूसरी सरकार के कार्यकाल में भी किये गये। प्रश्न यह है कि भारत की पूरी जमीन किसकी है ? यह जमीन भारत के लोगों की है जिसका प्रबन्धन उन्हीं के द्वारा चुनी गई सरकारें करती है। मगर बिहार में आगामी नवम्बर महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और मुसलमान मतदाताओं की संख्या यहां काफी है इसलिए चुनावी समीकरणों को देखते हुए विभिन्न राजनैतिक दल अपनी-अपनी चौसर बिछाने में लगे गए हैं। बिहार के प्रमुख क्षेत्रीय राजनैतिक दल राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने तो गांधी मैदान की रैली में यहां तक कह दिया कि यदि चुनावों के बाद उनके गठबन्धन की सरकार सत्ता में आयी तो वह इस कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। ऐसा कह कर राज्य के पूर्व उपमुख्यमन्त्री ने संसद की अवमानना करने का काम ही किया है क्योंकि संसद के दोनों सदनों ने नये कानून को बहुमत से बनाया है और तत्सम्बन्धी विधेयक को पारित करते समय राज्यसभा में भी पूरी बहस हुई। वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्य अल्लाह के नाम पर दान की गई जमीन का सदुपयोग समाज के हित में करने का है मगर इसके विपरीत वक्फ की जमीनों पर माफिया की तरह कुछ चन्द लोगों ने कब्जा जमाया हुआ है। अतः नये वक्फ कानून के विरोध में जाने वाले दलों को सोचना होगा कि वे जो कार्य कर रहे हैं क्या यह धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा नहीं देगा? हिन्दू और मुसलमान भारत के ही नागरिक हैं और सभी के बराबर अधिकार भी हैं। मगर बिहार में श्रीमान लालू यादव की पार्टी का जो वोट बैंक माना जाता है वह मुस्लिम-यादव गठजोड़ है। अतः आसानी से समझा जा सकता है कि उनके पुत्र तेजस्वी यादव की क्या मंशा है। वह यह कार्य अपने मूल वोट बैंक को साधे रखे रहने की वजह से ही कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनावों में श्री लालू यादव की पार्टी की सीटें भाजपा की सीटों से मात्र एक ज्यादा थी। इसके साथ ही बिहार में चुनाव जातिगत आधार पर ज्यादा लड़े जाते हैं । मगर वक्फ बोर्ड कानून का आंखें मींच कर इकतरफा विरोध करने की जवाबी प्रतिक्रिया भी तो हो सकती है?

बिकते रहना ही पाकिस्तान की तकदीर !

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जगह सेना अध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर को लंच पर बुलाया तो यह चर्चा होने लगी कि यदि ट्रम्प को भारत के साथ बात करनी होती तो वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाते। यह भी चर्चा हुई कि ट्रम्प भारत को दोस्त मानते हैं तो लंच पर मुनीर को क्यों बुलाया? ईरान पर हमले के बाद समझ में आया कि वह तो षड्यंत्र से भरा लंच था। अमेरिका ने टुकड़े दिखाए और मुनीर दौड़े चले गए। मामला सिर्फ इतना ही नहीं है। ईरानी मीडिया तो बड़े स्पष्ट शब्दों में आरोप लगा रहा है कि मई के अंतिम सप्ताह में पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष मुनीर ने ईरान के टॉप कमांडर मोहम्मद हुसैन बकरी से मुलाकात की थी और उन्हें एक स्मार्ट वॉच भेंट की थी। उस स्मार्ट वॉच में जीपीएस ट्रैकर लगा था। मुनीर ने उस जीपीएस ट्रैकर का एक्सेस इजराइल को दे दिया और तीन सप्ताह में ही इजराइल ने मोहम्मद हुसैन बकरी को मार गिराया। बकरी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस्लाम का झंडा लेकर घूमने वाला पाकिस्तान इतना बड़ा धोखा देगा या फिर मुनीर इजराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट की तरह काम करेंगे। बकरी ने इतिहास से सबक नहीं सीखा कि दुनिया में पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिस पर भरोसा करने वाले हमेशा ही धोखा खाते हैं, ऐसे ढेर सारे और भी प्रसंग हैं जो इजराइल-ईरान की जंग में पाकिस्तान की भितरघाती भूमिका को दर्शाते हैं। पाकिस्तान एक तरफ तो ईरान पर हमले की निंदा करता है और दूसरी तरफ वो सारी हरकतें करता है जो ईरान में तबाही बरपा सके। वैसे जनरल मुनीर वही कर रहे हैं जो उनके पूर्ववर्ती सेना अध्यक्ष करते रहे हैं। सेना ने पाकिस्तान की तासीर ही ऐसी बना दी है कि जो टुकड़े दिखाए, बेहतर कीमत दे उसके हाथ बिक जाओ। कल को कोई और बड़ी बोली लगा दे तो उसके गले लिपट जाओ, जब अमेरिका को अफगानिस्तान में सोवियत रूस को पस्त करने के लिए पाकिस्तान की जरूरत थी तो अमेरिका ने अपनी थैली खोल दी और पाकिस्तान उसकी गोद में जा लेटा और जब चीन ने दौलत की पोटली खोली तो बिना देर किए चीन की गोद में जा बैठा। पाकिस्तान जब आजाद हुआ था तब लेटने के लिए उसके पास केवल अमेरिका की गोद थी फिर भी वह गद्दारी से बाज नहीं आता था। अफगानिस्तान के एवज में वह अमेरिका से खूब धन-दौलत बटोरता रहा और इधर ओसामा बिन लादेन को अपने घर में छिपाता भी रहा। अमेरिका इस गद्दारी को समझ रहा था लेकिन वह भी कम बड़ा खिलाड़ी थोड़े ही है। उसने भी पाकिस्तान का खूब इस्तेमाल किया लेकिन अब पाकिस्तान के पास चीन की भी एक गोद है, अब गोद दो हैं तो उसकी बेवफाई भी बढ़ गई है। एक गोद नाराज हो जाए तो दूसरी गोद का सहारा मिल जाएगा। दोनों गोदें जानती हैं कि ये बेवफा है लेकिन क्या करें, कई बार बेवफाई भी बड़े काम की होती है। बेवफाई को थोड़ा बर्दाश्त करना वक्त की जरूरत बन जाती है। दोनों गोदों को पता है कि ये माल बिकाऊ है, जब कीमत लगाएंगे, अपनी गोद में बिठा लेंगे। लेकिन पाकिस्तान की इस बदनसीबी पर बहुत रोना आता है। मुझे तीन बार पाकिस्तान जाने का मौका मिला है, वहां की अवाम से बातचीत और मीडिया से रूबरू होने का मौका मिला है, अब भी परदेस में रह रहे पाकिस्तानियों से मुलाकात और बातचीत होती रहती है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने कंचन ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पैंपसखाना एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/06862)

डिजिटल भारत के 10 साल पूरे; पीएम मोदी ने कहा- अगला दशक होगा और भी परिवर्तनकारी

नई दिल्ली । डिजिटल इंडिया मिशन के 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जश्न मनाते हुए अपने आधिकारिक लिंक्डइन हैंडल पर डिजिटल इंडिया का एक दशक शीर्षक से एक ब्लॉग साझा किया है। उन्होंने डिजिटल इंडिया के दस वर्षों का सफर बयां किया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि किस प्रकार भारत 2014 में सीमित इंटरनेट पहुंच और डिजिटल साक्षरता से 2024 में डिजिटल प्रौद्योगिकी में वैश्विक अग्रणी बन गया है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले लोग इस बात पर संदेह करते थे कि भारतीय लोग तकनीक का सही इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। लेकिन सरकार ने लोगों पर भरोसा किया और अमीरों और गरीबों के बीच की खाई को भरने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया। आज, डिजिटल उपकरण 140 करोड़ भारतीयों के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन गए हैं। शिक्षा और व्यवसाय से लेकर सरकारी सेवाओं तक इसकी पहुंच है। उन्होंने बताया कि 2014 में भारत में करीब 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे। अब यह संख्या 97 करोड़ से ज्यादा हो गई है। हाई-स्पीड इंटरनेट गलवान और सियाचिन जैसे दूरदराज के इलाकों में भी पहुंच गया है। देश का 5जी रोलआउट दुनिया में सबसे तेज है। इसमें सिर्फ दो साल में करीब 5 लाख बेस स्टेशन स्थापित किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म पर जोर दिया। यह अब सालाना 100 अरब से अधिक लेनदेन संभालता है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के जरिए 44 लाख करोड़ सीधे लोगों को भेजे गए हैं। इससे बिचौलियों को हटाकर लगभग 3.5 लाख करोड़ की बचत हुई है। डीबीटी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी या अन्य लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दिए जाते हैं, बजाय किसी अन्य माध्यम से। उन्होंने बताया कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स और सरकारी ई

मार्केटप्लेस जैसे प्लेटफॉर्म छोटे व्यवसायों को बड़े बाजारों से जोड़कर उन्हें आगे बढ़ाने में कैसे मदद कर रहे हैं। ओएनडीसी ने हाल ही में 200 मिलियन लेन-देन को पार किया है, जबकि जीईएम ने केवल 50 दिनों में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की बिक्री कर ली है, जिसमें 1.8 लाख से अधिक महिलाओं के नेतृत्व वाले एमएसएमई सहित 22 लाख विक्रेताओं ने 46,000 करोड़ रुपये के ऑर्डर पूरे किए हैं। स्वामित्व योजना के तहत 2.4 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए हैं और 6 लाख से ज्यादा गांवों का मानचित्रण किया गया है। ओएनडीसी ,यह एक खुला नेटवर्क है जिसका उद्देश्य भारत में ई-कॉमर्स को बढ़ावा देना है। इसका लक्ष्य एक ऐसा मंच बनाना है जहां खरीदार और विक्रेता किसी भी प्लेटफॉर्म या ऐप का उपयोग करके स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकें, भले ही वे एक ही प्लेटफॉर्म पर न हों।

जीईएम,एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो भारत सरकार द्वारा सरकारी विभागों, संगठनों और सार्वजनिक उपक्रमों को वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए बनाया गया है। स्वामित्व योजना, जिसे सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक के साथ मानचित्रण- के रूप में भी जाना जाता है, एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में संपत्ति के मालिकों को कानूनी अधिकार प्रदान करना है। भारत के डिजिटल उपक्रम, जैसे आधार, CoWIN, डिजिलॉकर और FASTag अब अन्य देशों द्वारा उपयोग और अध्ययन किए जा रहे हैं। CoWIN ने 220 करोड़ प्रमाणपत्र जारी करके दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के प्रबंधन में मदद की, जबकि 54 करोड़ उपयोगकर्ताओं के साथ डिजिलॉकर में अब 775 करोड़ से अधिक दस्तावेज हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब दुनिया के शीर्ष 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक है, जहां 1.8 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हैं। देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत एआई मिशन के जरिए बहुत कम कीमत पर शक्तिशाली एआई टूल तक पहुंच प्रदान कर रहा है। इससे यह डिजिटल इनोवेशन के लिए वैश्विक केंद्र बन गया है। उन्होंने 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के भारत एआई मिशन जैसी पहलों द्वारा समर्थित एआई प्रतिभा में भारत की बढ़ती ताकत पर जोर दिया। उन्होंने लिखा कि भारत ने वैश्विक स्तर पर बेजोड़ कीमतों पर 34,000 जीपीयू तक पहुंच को सक्षम किया है, प्रति जीपीयू घंटे 1 अमेरिकी डॉलर से भी कम है। इससे यह न केवल सबसे सस्ती इंटरनेट अर्थव्यवस्था बन गया है, बल्कि सबसे किफायती कंप्यूट गंतव्य भी बन गया है। पीएम मोदी ने कहा कि अगले 10 साल और भी अधिक परिवर्तनकारी होंगे। उन्होंने इनोवेटर्स और उद्यमियों से ऐसी तकनीक बनाने का आह्वान किया जो लोगों की मदद करे और भारत को डिजिटल दुनिया में एक विश्वसनीय वैश्विक भागीदार बनाए।

उपलब्धिः भारतीय अर्थव्यवस्था विदेशी निवेश के लिए भरोसेमंद; अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों ने बरकरार रखा ग्रेड

नई दिल्ली । दुनिया की तीन प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों स्टैंडर्ड एंड पुअर्स (एसएंडपी), मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस और फिच रेटिंग्स ने भारत को इन्वेस्टमेंट ग्रेड श्रेणी में बनाए रखा है। यह रेटिंग इस बात का संकेत है कि भारत की अर्थव्यवस्था विदेशी निवेश के लिए भरोसेमंद मानी जा रही है। लेकिन उसमें अब भी सुधार की गुंजाइश है। हालांकि, भारत की स्थिति अभी भी शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं जैसे अमेरिका, जर्मनी और चीन से काफी नीचे है। तीनों प्रमुख एजेंसियों ने हाल में जून तक की रिपोर्ट जारी की है। एसएंडपी और फिच ने भारत को बीबीबी रेटिंग को बनाए रखा है। मूडीज ने बीएए3 ग्रेड में रखा है। तीनों के ग्रेड का मतलब देश की रेटिंग स्थिर श्रेणी में है। भारत को ऊंची रेटिंग पाने के लिए अर्थव्यवस्था को और मजबूत करना होगा, खासकर वित्तीय घाटे और सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के अनुपात के कर्ज के मोर्चे पर ज्यादा सुधार की जरूरत है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के लिए यह जरूरी है कि वह आगे चलकर केवल ए अथवा एए जैसी उच्च रेटिंग प्राप्त करे ताकि वैश्विक निवेशकों का भरोसा और मजबूत हो सके। इन ग्रेडों को कई श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे एएए ग्रेड का अर्थ होता है कि देश की गुणवत्ता सर्वोच्च है और उसमें निवेश करना बेहद सुरक्षित है। एए उच्च गुणवत्ता की श्रेणी में होता है, जिसमें जोखिम बहुत कम होता है। केवल ए की रेटिंग यानी देश की आर्थिक स्थिति संतुलित है, लेकिन उसमें जोखिम मौजूद है। बीबीबी को निवेश योग्य श्रेणी माना जाता है, लेकिन सुरक्षा सीमित होती है और जोखिम मध्यम स्तर पर रहता है। बीबी या इससे नीचे की रेटिंग को सट्टा श्रेणी माना जाता है, जिसमें निवेश करना अधिक जोखिम भरा होता है। डी, एसडी या आरडी रेटिंग का मतलब है कि संस्था डिफॉल्ट कर चुकी है या डिफॉल्ट की स्थिति में है। जर्मनी को सभी एजेंसियों ने एएए (सर्वोत्तम) श्रेणी में रखा है, जबकि अमेरिका को एए प्लस और चीन को ए प्लस मिला है। वहीं, रूस की स्थिति सबसे खराब है। उसे एसडी यानी सिलेक्टिव डिफॉल्ट और आरडी (रिस्ट्रिक्टेड डिफॉल्ट) जैसी रेटिंग मिली है। वर्तमान में पाकिस्तान की स्थिति आर्थिक रूप से काफी खस्ता हाल है। मूडीज ने पाकिस्तान को सीएए3 रेटिंग दी है, जो अत्यंत उच्च जोखिम वाली श्रेणी में आती है, यानी भविष्य में और जोखिम की आशंका जताई गई है। इसी तरह स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और फिच ने पाकिस्तान को सीसीसी श्रेणी यानी ऋण भुगतान में बेहद कमजोर है। चीन अब भी मध्यम से उच्च साख वाले देशों की श्रेणी में है। मूडीज ने चीन को ए1 रेटिंग दी है।

एटीएफ की कीमत में 7.5 प्रतिशत की भारी वृद्धि, वाणियिक एलपीजी की दर में 58.5 रुपये की हुई कटौती

नई दिल्ली । विमान ईंधन (एटीएफ) की कीमत में मंगलवार को 7.5 प्रतिशत की बड़ी वृद्धि की गई। दूसरी ओर, वाणियिक प्रतिष्ठानों में इस्तेमाल होने वाला एलपीजी 58.50 रुपये प्रति सिलेंडर सस्ता हो गया है। अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क दरों में बदलाव के कारण कीमतों में उतार-चढ़ाव हुआ है। सरकारी स्वामित्व वाले खुदरा ईंधन विक्रेताओं के अनुसार, कीमतों में तीन दौर की कटौती के बाद राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) की कीमत 6,271.5 रुपये प्रति किलोलीटर या 7.5 प्रतिशत बढ़कर 89,344.05 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई। राजधानी देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। यह वृद्धि अप्रैल से अब तक तीन मासिक किस्तों में लागू की गई कुल कटौती का आधा है। एटीएफ की कीमत आखिरी बार एक जून को 2,414.25 रुपये प्रति किलोलीटर (2.82 प्रतिशत) घटाकर 83,072.55 रुपये प्रति किलोलीटर कर दी गई थी। उससे पहले एक मई को कीमतों में 4.4 प्रतिशत (3,954.38 रुपये प्रति किलोलीटर) की कटौती की गई थी और एक अप्रैल को 6.15 प्रतिशत (5,870.54 रुपये प्रति किलोलीटर) की भारी कटौती की

गई थी। एटीएफ की कीमत में यह वृद्धि पिछले महीने ईरान पर इस्राइल के हमले के बाद अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में आई तेजी कारण की गई है। इस वृद्धि से वाणियिक एयरलाइनों पर बोझ बढ़ेगा, जिनके परिचालन लागत में ईंधन का हिस्सा लगभग 40 प्रतिशत होता है। मूल्य वृद्धि के प्रभाव पर एयरलाइनों से तत्काल कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हो सकी। मुंबई में एटीएफ की कीमत 77,602.73 रुपये प्रति किलोलीटर से बढ़कर 83,549.23 रुपये प्रति किलोलीटर कर दी गई, जबकि चेन्नई और कोलकाता में इसकी कीमत क्रमशः 92,526.09 रुपये और 92,705.74 रुपये प्रति किलोलीटर कर दी गई। वैट जैसे स्थानीय करों के आधार पर दरें अलग-अलग शहरों में अलग-अलग होती हैं। इसके साथ ही तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले वाणियिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 58.5 रुपये की कटौती की है।

अब राष्ट्रीय राजधानी में वाणियिक एलपीजी की कीमत 1,665 रुपये और मुंबई में 1,616.50 रुपये होगी। यह वाणियिक एलपीजी दरों में लगातार चौथी कटौती है। पिछली बार 1 जून को 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत में 24 रुपये की कटौती की गई थी। उससे पहले 1 मई को 14.50 रुपये और 1 अप्रैल को 41 रुपये प्रति सिलेंडर की कटौती की गई थी। कुल मिलाकर, अप्रैल से अब तक कीमतों में 138 रुपये प्रति सिलेंडर की कटौती की गई है। जबकि तेल की कीमतें उबल रही हैं, गर्मी के महीनों में कम मांग के कारण बेंचमार्क एलपीजी की दरें कम हो गई हैं। एटीएफ और एलपीजी की कीमतें वैट सहित स्थानीय करों के आधार पर राज्य दर राज्य अलग-अलग होती हैं। हालांकि, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 853 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम पर अपरिवर्तित रही। अप्रैल में घरेलू रसोई गैस की कीमत में 50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी।सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) हर महीने की पहली तारीख को बेंचमार्क अंतरराष्ट्रीय ईंधन की औसत कीमत और विदेशी विनिमय दर के आधार पर एटीएफ और रसोई गैस की कीमतों में बदलाव करती हैं। वहीं, पेट्रोल और डीजल की घरेलू दरें स्थिर बनी हुई हैं। पिछले साल मार्च के मध्य में आम चुनावों से पहले कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई थी। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 87.62 रुपये प्रति लीटर है।

कमजोर ऋण वृद्धि और मार्जिन से बैंकिंग सेक्टर की आय पर पड़ा असर, पीएटी में दो प्रतिशत की गिरावट संभव

नई दिल्ली । चालू वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में बैंकों की आय में गिरावट देखने को मिल सकती है। आईआईएफएल कैपिटल की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार कमजोर कमजोर ऋण वृद्धि, कम मार्जिन, मौसमी रूप से नरम शुल्क आय और उच्च स्लिपेज बैंकिंग क्षेत्र के प्रदर्शन पर असर डाल सकते हैं। इसमें बताया गया कि पहली तिमाही में बैंकों का कर पश्चात लाभ (पीएटी) साल-दर-साल आधार पर 2 फीसदी और तिमाही आधार पर 4 फीसदी तक घट सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि तिमाही के दौरान कारोबारी गति धीमी रही। वहीं, प्रणाली-व्यापी ऋण और जमा वृद्धि कुछ हद तक स्थिर रही। प्रणाली ऋण वृद्धि दर पिछले वर्ष को 11 प्रतिशत से घटकर 9.6 प्रतिशत रह गई। 3 जून तक की तिथि पर, ऋण वृद्धि मात्र 0.4 प्रतिशत रही, जबकि आमतौर पर पहली तिमाही में यह 1.5 से 2.0 प्रतिशत के बीच होती है। सभी क्षेत्रों में ऋण वृद्धि धीमी रही, सिवाय एमएसएमई ऋण के, जिसमें वृद्धि दर मध्यम स्तर पर रही। गैर-सरकारी वित्तीय संस्थान (एनबीएफसी) ऋण स्थिर रहा, बचड़ी कंपनियों को सिर्फ 1 प्रतिशत का लाभ हुआ, वाहन ऋण में 6 प्रतिशत, और आवास व असुरक्षित ऋणों में 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। रिपोर्ट के अनुसार पहली तिमाही में बैंकों के शुद्ध ब्याज मार्जिन में 8 से 25 आधार अंक की गिरावट हो सकती है। ऋण दरों में 10 से 20 आधार अंक की गिरावट ने जमा दरों में कमी से होने वाले लाभ को भी संतुलित कर दिया। दिसंबर 2024 से बचत खाता दरों में 20 से 350 आधार अंकों की कटौती की गई है। वहीं खुदरा सावधि जमा दरों में भी 20 से 100 आधार अंक की गिरावट आई है। थोक जमा दरों में भी 1 प्रतिशत तक की नरमी देखी गई। सिस्टम तरलता औसतन 2 लाख करोड़ रुपये के अधिशेष में रही, जो पिछली तिमाही में 1.7 लाख करोड़ के घाटे में थी। लेकिन कम ऋण मांग और घटती जमा दरों के चलते मई तक औसत मार्जिन में गिरावट आई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के औसत बकाया प्रसार में 9 आधार अंकों की गिरावट आई है, जबकि निजी बैंकों के लिए यह गिरावट 26 आधार अंकों की है। मौसमी रूप से कमजोर शुल्क आय और अस्थिर परिचालन खर्चों के कारण बैंकों की कोर प्री-प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट वृद्धि लगभग स्थिर रह सकती है। इसके अलावा, मौसमी वृद्धि और पुराने प्रावधानों के कारण ऋण लागत में वृद्धि होने की संभावना है। रिपोर्ट का अनुमान है कि दूसरी तिमाही तक मार्जिन में कुल 22 से 35 आधार अंकों की और गिरावट आ सकती है। हालांकि तीसरी तिमाही से मार्जिन स्थिर होने और चौथी तिमाही से फिर से बढ़ने की संभावना जताई गई है।

तीन महीनों में शेयर बाजार में 72 लाख करोड़ की रिकॉर्ड रैली, लेकिन वैल्यूएशन पर मंडरा रहा खतरा

बिजनेस डेस्क । भारतीय शेयर बाजार ने बीते तीन महीनों में ऐतिहासिक रफ्तार पकड़ी है। सेंसेक्स ने 12,000 अंकों की छलांग लगाई है, जिससे बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण लगभग 72 लाख करोड़ बढ़कर 461 लाख करोड़ हो गया है। हालांकि, यह तेजी जितना लाभदायक रही है, उतनी ही चिंता का कारण भी बन गई है- खासकर उन निवेशकों के लिए जिनके पास नकदी पड़ी है या जो नए निवेश के लिए सही मौके की तलाश में थे। साथ ही तेजी ने वैल्यूएशन और फंडामेंटल्स के बीच गैप पैदा कर दिया है। एक्सपर्ट का कहना है कि मार्केट अपनी क्षमता से ज्यादा ऊपर हो गया, इसलिए वैल्यूएशन को लेकर खतरा है। घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 3.5 लाख करोड़ का निवेश किया। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भी तीन महीनों से लगातार खरीदारी जारी रखी है। म्यूचुअल फंड्स के पास मई में 2.17 लाख करोड़ कैश उपलब्ध था, जबकि मासिक SIP फ्लो 26,000 करोड़ से अधिक रहा। JM फाइनेंशियल के वेंकटेश बालासुब्रमण्यम के अनुसार, यह रैली पूरी तरह लिक्विडिटी-ड्रिवन है। बाजार की मौजूदा स्थिति ने वैल्यूएशन और फंडामेंटल्स के बीच खाई को गहरा कर दिया है। एनालिस्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सभी अपने औसत वैल्यूएशन से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। कोटक AMC के नीलेश शाह कहते हैं कि पिछले पांच सालों के रिटर्न अगले कुछ सालों में दोहराए जाने की चांसेज कम हैं। मार्केट अब फेयरली वैल्यूड या थोड़ा ओवरवैल्यूड है। रिटर्न अब अर्निंग्स ग्रोथ पर निर्भर करेगा, जो 8-12 फीसदी के दायरे में रह सकता है। शाह निवेशकों को सलाह देते हैं कि वे इक्विटी के अलावा REITs, InvITs, डेट म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड और ETFs में डायवर्सिफाई करें। RBI द्वारा हाल ही में की गई दरों में कटौती और नकद आरक्षित अनुपात में बदलाव ने बाजार में तरलता बढ़ाई है जिसका सबसे ज्यादा फायदा फाइनेंशियल सेक्टर को हुआ है। क्वांटिस रिसर्च के कार्तिक जोनगडला का कहना है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियर्स जैसे PFC और REC में अच्छा मौका है।

PSU बैंक इंडेक्स भी छह महीने के हाई पर है। 9 जुलाई की टैरिफ डेडलाइन और Q1 रिजल्ट सीजन से पहले सतर्कता जरूरी है। IT सेक्टर, जो इस साल अब तक सुस्त रहा, अब बेहतर डिविडेंड यील्ड और कम वैल्यूएशन के चलते निवेश के लायक बन रहा है। केमिकल सेक्टर में दो साल की गिरावट के बाद स्थिरता और संभावित रिकवरी दिख रही है। फार्मा और केमिकल जैसे एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड सेक्टर में अमेरिकी टैरिफ को लेकर जोखिम बना हुआ है।

निजी निवेश बढ़ा पर अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी, भारत में हुए सुधारों पर स्पेन में बोलीं सीतारमण

नई दिल्ली । स्पेन, पुर्तगाल और ब्राजील की आधिकारिक यात्रा पर गईं वित्त मंत्री मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पेन के सेविले में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंच के शिखर सम्मेलन के दौरान सतत विकास के लिए निजी पूंजी जुटाने की जोरदार वकालत की। उन्होंने एफएफडी4 परिणाम से कार्यान्वयन तक सतत विकास के लिए निजी पूंजी की क्षमता को अनलॉक करना शीर्षक पर अपनी राय रखी। वैश्विक नेताओं और निवेशकों को संबोधित करते हुए, सीतारमण ने कहा कि हाल के वर्षों में निजी निवेश ने उत्साहजनक वृद्धि दिखाई है, लेकिन अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में, मंत्री ने कहा, निजी पूंजी निवेश अब भी आवश्यकता से काफी कम है, कम और मध्यम आय वाले देशों को अनुपातहीन रूप से छोटा हिस्सा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि निवेश बाधाओं को दूर करने और विकास प्राथमिकताओं के साथ वित्तीय प्रवाह को बेहतर करने के प्रयासों की तत्काल आवश्यकता है। अपनी यात्रा के दौरान सीतारमण ने उभरते बाजारों में कथित निवेश जोखिमों को संबोधित करने के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने इन चुनौतियों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सीतारमण ने कहा, भारत ने स्वतंत्र विनियामकों की स्थापना, पारदर्शी बोली प्रक्रियाओं को लागू करने, अनुबंधों को मानकीकृत करने और व्यापार करने में आसानी में सुधार करके इस चुनौती का समाधान किया है। इन सुधारों ने निवेशकों के विश्वास को काफी बढ़ाया है और लेन-देन की लागत को कम किया है। वित्त मंत्री ने मजबूत घरेलू वित्तीय प्रणालियों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। भारत ने बुनियादी ढांचे और उद्योग में बड़े पैमाने पर वित्तपोषण का समर्थन करने के लिए अपने बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने और पूंजी बाजारों को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने कहा कि भारत के विनियामक ढांचे अब निवेशक सुरक्षा को नवाचार और लचीलेपन के साथ बेहतर ढंग से संतुलित करते हैं। इससे दीर्घकालिक निवेश के लिए एक सक्षम वातावरण बनता है। वित्त मंत्री ने कहा, हमारे विनियामक ढांचे बाजार की जरूरतों के साथ विकसित हुए हैं- निवेशक सुरक्षा को नवाचार और लचीलेपन के साथ संतुलित करते हुए- दीर्घकालिक निवेश के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बनाते हैं। सीतारमण ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में भारत में हुए परिवर्तन का जिक्र करते हुए कहा, 2014 में स्थापित केवल 2.8 गीगावॉट सौर ऊर्जा से, भारत ने अपनी क्षमता को 110 गीगावॉट से अधिक तक बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा, ःयह सफलता स्पष्ट राष्ट्रीय लक्ष्यों, सुव्यवस्थित खरीद और सरकार समर्थित कदमों से मिली। इस मॉडल ने पेंशन और सॉवरेन वेल्थ फंड सहित संस्थागत निवेशकों को आकर्षित किया।ः एफएफडी4 शिखर सम्मेलन के दौरान सीतारमण ने विभिन्न वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कीं। उन्होंने न्यूजीलैंड के विज्ञान, नवाचार और प्रौद्योगिकी, विश्वविद्यालय, सांख्यिकी और प्रशांत क्षेत्र के लोगों के मंत्री शेन रेती से मुलाकात की।

दोनों मंत्रियों ने रक्षा, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और कृषि में सहयोग पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और मजबूत लोगों के बीच संबंधों की पुष्टि की। सीतारमण ने वहूमाल सिटी में भारत के बढ़ते अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के बारे में भी बात की और बैंकिंग, बुलियन एक्सचेंज, पूंजी बाजार, फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र, बीमा और पुनर्बीमा में निवेश के अवसरों पर प्रकाश डाला। उन्होंने शैक्षिक संबंधों के महत्व पर भी ध्यान दिया, जिसमें कई भारतीय छात्र न्यूजीलैंड में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने जर्मनी की संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्री रीम अलाबली-राडोवन के साथ भी बातचीत की। सीतारमण ने उन्हें उनकी नई भूमिका के लिए बधाई दी और भारत-जर्मनी हरित और सतत विकास साझेदारी के तहत सहयोग पर चर्चा की। सीतारमण 30 जून से 5 जुलाई तक की इस आधिकारिक यात्रा के दौरान आर्थिक मामलों के विभाग के एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं।

एक नजर

भारत का विनिर्माण क्षेत्र जून में 14 महीने के उच्चतम स्तर पर, निर्यात और नौकरियों में उछाल

नई दिल्ली । भारत के विनिर्माण क्षेत्र ने वित्त वर्ष की पहली तिमाही में मजबूत वृद्धि दिखी। एचएसबीसी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) के आंकड़ों से इसकी पुष्टि हुई। यह इंडेक्स मई में 57.6 से जून में 58.4 पर पहुंच गया। एचएसबीसी के अनुसार, यह 14 महीनों में उच्चतम स्तर है। पीएमआई का आंकड़ा 54.1 के दीर्घकालिक औसत से काफी ऊपर है। यह व्यापार स्थितियों में मजबूत सुधार के संकेत देता है। जून में अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर में तेज वृद्धि दिखी। 2005 में सर्वेक्षण शुरू होने के बाद से निर्यात मांग में तीसरी सबसे तेज गति से वृद्धि देखी गई। इसमें कंपनियों की ओर से मांग के प्रमुख स्रोत के रूप में ज्यादातर अमेरिका का उल्लेख किया गया। इस मजबूत वैश्विक रुचि ने समग्र बिक्री और उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद की। अप्रैल 2024 के बाद से उत्पादन की मात्रा सबसे तेज दर से बढ़ी, जो मुख्य रूप से मध्यवर्ती सामान निर्माताओं की ओर से संचालित है। हालांकि, उपभोक्ता और पूंजीगत सामान उत्पादकों ने धीमी वृद्धि देखी। सक्रिय विपणन प्रयासों और बढ़ते निर्यात द्वारा समर्थित नए ऑर्डर भी अधिक तेजी से बढ़े। मांग में मजबूत वृद्धि से रोजगार में रिकॉर्ड वृद्धि हुई। मई में स्थिरता के बाद, जून में काम का बैकलॉग बढ़ गया, जिससे कई कंपनियों को अधिक कर्मचारियों को काम पर रखना पड़ा। इस भर्ती का अधिकांश हिस्सा अल्पकालिक जरूरतों के लिए था, जिसका उद्देश्य बढ़े हुए कार्यभार को संभालना था। एचएसबीसी के आंकड़ों के अनुसार लोहे और स्टील जैसे कच्चे माल की कीमतें उच्च बनी रहीं। कुल इनपुट लागत मुद्रास्फीति फरवरी के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई और यह ऐतिहासिक औसत से नीचे रही। इसके बावजूद, बिक्री की कीमतें बढ़ती रहीं क्योंकि कंपनियों ने अपने ग्राहकों को उच्च लागत- जिसमें माल ढुलाई, श्रम और सामग्री शामिल है की जानकारी दी। कई फर्मों ने कहा कि वे मजबूत मांग के कारण कीमतें बढ़ाने में सक्षम थे। निर्माताओं ने कच्चे माल की अपनी खरीद भी बढ़ा दी, जो 14 महीनों में खरीद गतिविधि में सबसे मजबूत वृद्धि को दर्शाता है।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की सुगबुगाहट के बीच बाजार में लौटी हरियाली; सेंसेक्स-निफ्टी में तेजी

मुंबई । हफ्ते के पहले दिन हुई गिरावट के बाद घरेलू शेयर बाजार में मंगलवार को हरियाली लौटी। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर सहमति की सुगबुगाहट के बीच बाजार सकारात्मक रुख के साथ खुले। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 177.79 अंक चढ़कर 83,784.25 पर पहुंचा, जबकि निफ्टी 51.2 अंक चढ़कर 25,568.25 पर पहुंचा। शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया भी 42 पैसे बढ़कर 85.34 पर पहुंचा। वैश्विक बाजारों में तेजी के बीच मंगलवार को शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार के बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी दिखी। वे पिछले कारोबारी सत्र में आई गिरावट की भरपाई करते नजर आए। इसके अलावा ब्लू-चिप शेयरों रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक में खरीदारी ने भी शुरुआती कारोबार के दौरान बाजार में सकारात्मकता को रफ्तार दी। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 177.79 अंक चढ़कर 83,784.25 पर पहुंच गया। 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 51.2 अंक बढ़कर 25,568.25 पर पहुंच गया।

किसे फायदा-किसे नुकसान?

सेंसेक्स की कंपनियों में एशियन पेंट्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक और एचसीएल टेक के शेयरों में तेजी रही। ट्रेंट, एक्सिस बैंक, इटरनल और टाटा स्टील के शेयरों में गिरावट देखी गई। एक्सचेंज डेटा के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने सोमवार को 831.50 करोड़ रुपये के इक्विटी बेचे।

एशियाई और अमेरिकी बाजारों का हाल

एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी और शंघाई का एसएसई कंपोजिट सूचकांक सकारात्मक क्षेत्र में कारोबार कर रहा था, जबकि जापान का निक्केई 225 सूचकांक लाल निशान पर दिखा। सोमवार को अमेरिकी बाजार बढ़त के साथ बंद हुए थे। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.24 प्रतिशत गिरकर 67.61 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।

नियमों का पालन न करने पर काटी गई चिन्नास्वामी स्टेडियम की बिजली; हाईकोर्ट ने बेसकॉम को लगाई फटकार

बंगलूरू । बंगलूरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ने एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम की बिजली आपूर्ति काट दी है। इस की वजह अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करना बताया जा रहा है। चिन्नास्वामी स्टेडियम का कामकाज कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ की ओर से देखा और संभाला जाता है। यह कार्रवाई तब की गई, जब अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग के महानिदेशक ने बेसकॉम के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर सुझाए गए अग्नि सुरक्षा उपायों को लागू न करने के कारण स्टेडियम की बिजली काटने का निर्देश दिया। मौजूदा वक्त में स्टेडियम को जनरेटर के जरिए बिजली की आपूर्ति की जा रही है। इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने अग्नि सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन के बावजूद स्टेडियम को बिजली आपूर्ति जारी रखने के लिए बेसकॉम को जमकर फटकार लगाई थी। मामला बेसकॉम की ओर से जारी किए गए डिस्कनेक्शन नोटिस को चुनौती देने वाली केएससीए की याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया। जस्टिस एस. सुनील दत्त यादव की एकल पीठ ने याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, बेसकॉम के नोटिस और अदालत में आवेदन दायर करने के बाद कुछ घटनाक्रम हुए हैं। 12 जून को बेसकॉम ने कनेक्शन काटने का नोटिस जारी किया और बिजली काट दी। 17 जून को इसे चुनौती देते हुए आवेदन दायर किया गया। उसी दिन बिजली कनेक्शन बहाल कर दिया गया। पीठ ने कहा कि बेसकॉम ने यह जानते हुए भी बिजली की आपूर्ति की कि केएससीए ने नियमों का पालन नहीं किया है। इस पर बेसकॉम के वकील लिखित ने अदालत को बताया कि केएससीए के अनुरोध पर बिजली कनेक्शन बहाल किया गया था और इसे फिर से काट दिया जाएगा। इसके बाद पीठ ने कहा कि सरकार को अग्नि सुरक्षा मंजूरी पत्र जारी करना चाहिए। अगर आप सरकार से परामर्श किए बिना बिजली प्रदान करते हैं, तो अदालत चुप नहीं रहेगी। जो अनहोनी पहले हुई है, वही काफी है। अगर कोई और दुर्घटना होती है तो कौन जिम्मेदार होगा? अगर अग्नि सुरक्षा उपाय नहीं किए गए, तो स्टेडियम को अंधेरे में रहने दें। बिजली कनेक्शन बहाली के लिए अग्नि सुरक्षा उपायों को मानना ही एकमात्र विकल्प बचा है। जोखिमों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। केएससीए के वकील ने दलील दी कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि बेसकॉम और अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग को कोई भी कार्रवाई न करने का निर्देश दिया जाए। पीठ ने जवाब दिया, अदालत इस मामले में आगे कुछ नहीं कहेगी। बेसकॉम के वकील ने मौखिक आश्वासन दिया है कि वे बिजली कनेक्शन काट देंगे, लेकिन पहले सरकार से पूछिए। अगर सरकार निर्देश देती है, तो ऐसा किया जाएगा। अन्यथा बेसकॉम को गलती के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अग्नि सुरक्षा एवं आपातकालीन सेवा विभाग के महानिदेशक ने 10 जून 2025 को बेसकॉम के प्रबंध निदेशक को एक निर्देश जारी किया था। इसमें 11 मई 2023 को विभाग के परामर्श पत्र में सुझाए गए अग्नि सुरक्षा उपायों को लागू करने में लापरवाही की वजह से 7 जुलाई 2011 से केएससीए को प्रदान की जा रही बिजली आपूर्ति बंद करने को कहा गया था। इसके बाद बेसकॉम ने 12 जून को केएससीए को कनेक्शन काटने का नोटिस जारी किया।

इस अरबपति ने उद्योग जगत में मचाई हलचल, कमाई के मामले में चौंकाया, पीछे रह गए अंबानी -अडानी

बिजनेस डेस्क। 2025 की पहली छमाही में एक भारतीय उद्योगपति ने कमाई के मामले में सबको चौंका दिया है। वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव के बावजूद, उनकी संपत्ति में 78 फीसदी की जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने इस दौर में मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया है। ये अरबपति हैं सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया के सह-संस्थापक और प्रेसिडेंट सत्यनारायण नुवाल। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के अनुसार, नुवाल की संपत्ति इस साल की पहली छमाही में 78.4फीसदी बढ़कर 7.90 अरब डॉलर (करीब 66,000 करोड़) हो गई।

गेंदबाजों से आईपीएल का खुमार उतारने के लिए टीम इंडिया की खास रणनीति, दो रंग की गेंद से किया अभ्यास

बर्मिंघम ।

भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला बुधवार से बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेला जाएगा। इसको लेकर भारतीय टीम जमकर अभ्यास कर रही है। खासतौर पर गेंदबाज जमकर पसीना बहा रहे हैं। लीड्स में गेंदबाजों के खराब प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम मैनेजमेंट उन पर से आईपीएल का खुमार उतारने के लिए उनसे दो रंग की गेंद से अभ्यास करा रहा है। इस गेंद की एक तरफ सफेद रंग और दूसरी तरफ लाल रंग है। भारतीय टीम के सहायक कोच रेयान टेन डेशकाटे ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको लेकर बड़ा खुलासा किया। दरअसल, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले भारतीय तेज गेंदबाज आईपीएल की लाइन-लेंथ से छुटकारा पाने के लिए दो रंग की गेंदों से अभ्यास करते दिखे। सत्र की शुरुआत में जसप्रीत बुमराह के आधा सफेद और आधा लाल रंग की गेंद से गेंदबाजी की। इसके बाद टीम के अन्य गेंदबाजों ने भी दो रंगों की गेंद से गेंदबाजी की। अभ्यास सत्र में एक से अधिक रंग वाली गेंदों का उपयोग करना एक आम बात है। भारतीय तेज गेंदबाज इंग्लैंड दौरे की शुरुआत से ऐसा कर रहे हैं। भारतीय तेज गेंदबाज सफेद गेंद के लंबे सत्र (चैंपियंस ट्रॉफी और आईपीएल) के बाद इंग्लैंड दौरे पर आए हैं। भारत के सहायक कोच डेशकाटे ने कहा कि दो रंग की गेंदों से अभ्यास करने से लाल गेंद (टेस्ट मैच) के खेल से सफेद गेंद (सीमित ओवरों के मैच) की आदतों को खत्म करने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा, यह कोई नई बात नहीं है। सभी गेंद निर्माता ऐसी गेंदें बनाते हैं। हम गेंदबाजों को सीमित ओवरों वाले लाइन लेंथ की आदत में सुधार करना चाहते हैं। यह आपको संकेत देने का सबसे आसान तरीका है। हमारे खिलाड़ी आईपीएल के लंबे सत्र के बाद यहां आए हैं। गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल की देख रेख में गेंदबाज पिछले दो हफ्तों से इसका उपयोग कर रहे हैं। वहीं, इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर मोईन अली ने सोमवार को अपने घरेलू मैदान पर मेजबान टीम के अभ्यास सत्र का अचानक दौरा किया।

इंग्लैंड को एजबेस्टन की पिच पर स्पिन की उम्मीद है और मोईन को भी यही लगता है। उनके इनपुट पर इंग्लिश टीम काफी भरोसा कर रही है। इंग्लैंड को उम्मीद है कि तीसरे दिन से स्पिनरों को मदद मिलने लगेगी। मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम और स्पिन गेंदबाजी कोच जीतन पटेल को मोहन के साथ लंबी बातचीत करते देखा गया। हालांकि, मोईन टीम के साथ कोचिंग भूमिका में नहीं आ रहे हैं। शीर्ष स्तर से संन्यास के बाद वह दुनिया भर की टी20 लीगों में खेलते हैं। वह आईपीएल 2025 का भी हिस्सा थे। दो रंग की गेंद से अभ्यास करना आधुनिक क्रिकेट में एक बहुत ही उपयोगी तरीका बन गया है, जो तकनीकी सुधार, बैटिंग स्किल और मैच की गंभीर परिस्थितियों के लिए खिलाड़ी को मानसिक रूप से तैयार करता है। गंभीर परिस्थितियों में इससे तुरंत कोई फैसला लेने में मदद मिलती है। कोच भी रियल टाइम में गेंदबाज की सीम रिलीज या बल्लेबाजों की फुटवर्क तकनीक में गलती पकड़ सकते हैं। खासकर युवा खिलाड़ियों के लिए यह बेहद फायदेमंद है। आइए जानते हैं कि गेंदबाजों को दो रंग की गेंद से अभ्यास **सीम पोजिशन का बेहतर कंट्रोल**

गेंदबाज अपनी गेंदबाजी एक्शन में सीम की स्थिति को बेहतर तरीके से देख और सुधार सकता है। इस गेंद से अभ्यास करने से यह साफ दिखता है कि सीम सीधी जा रही है या झुक रही है।

रिलीज पॉइंट की पहचान

गेंद छोड़ते समय हाथ से गेंद किस तरह निकल रही है, इसका अंदाजा गेंद की दो रंगों के कारण साफ नजर आता है। इससे कलाई की स्थिति और अंगुली की स्थिति पर काम करना आसान होता है।

स्विंग और स्पिन वेरिएशन में सुधार

गेंदबाज को तुरंत पता चलता है कि उसकी गेंद कितनी और किस दिशा में स्विंग या स्पिन हो रही है। इनस्विंग, आउटस्विंग या रिवर्स स्विंग का असर आसानी से देखा जा सकता है। खासकर स्पिन गेंदबाजों के लिए गेंद की हवा में फ्लाइट और ड्रिफ्ट साफ दिखती है। इससे लूप, डिप और ड्रिफ्ट पर बेहतर कंट्रोल आता है। इतना ही नहीं तेज गेंदबाजों और कोच को इससे स्लोअर वन, कटर्स, सीम पर या स्कैमबल्ड सीम जैसी वेरिएशंस का असर रंगों के चलते तुरंत दिखता है। गेंदबाजों को अपने वेरिएशंस और उसके प्रभाव को बेहतर तरीके से समझ पाने में मदद मिलती है।

वीडियो एनालिसिस में भी होती है आसानी

रिकॉर्डिंग के दौरान गेंद की लाइन-लेंथ और सीम मूवमेंट का विश्लेषण बहुत आसान हो जाता है। गेंदबाज अपनी तकनीकी गलतियों को खुद देखकर सुधार कर सकता है।

एक नजर

फेबियो फोगनिनी को हराने में कार्लोस अल्काराज को करनी पड़ी मशक्कत

नई दिल्ली । विंबलडन 2025 का आगाज हो चुका है। इस दौरान गत चैंपियन कार्लोस अल्काराज को टूर्नामेंट के पहले दौर के मुकाबले में अपने से 16 साल बड़े फेबियो फोगनिनी को हराने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। जिस कारण ये मुकाबला पांच सेटों तक खिंच गया आखिर में 22 वर्षीय स्पेनिश खिलाड़ी अल्काराज ने आखिर में साढ़े चार घंटे तक मेहनत करने के बाद 7-5, 6-7, 7-5, 2-6, 6-1 से जीता और अगले राउंड में जगह बना ली। 1968 में टेनिस के पेशेवर बनने के बाद से लगातार तीन विंबलडन खिताब जीतने वाले पांचवें खिलाड़ी बनने की कोशिश में जुटे अल्काराज लगातार 18 मैचों की जीत के साथ ऑल इंग्लैंड क्लब पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान वह दूसरे वरीय खिलाड़ी कई बार लय में नहीं दिखे। 22 वर्षीय खिलाड़ी को 2-1 से पिछड़ने के बाद दो ब्रेक प्वाइंट बचाने पड़े और अगले सर्विस गेम में तीन और ब्रेक प्वाइंट बचाने पड़े, जिसके बाद उन्होंने एक बेहतरीन ड्रॉप शॉट और उसके बाद एक लॉब के साथ 6-5 की बढ़त हासिल कर ली, जबकि सेंटर कोर्ट पर मौजूद फैंस सामान्य सर्विस के शुरू होने की उम्मीद कर रहे थे। बता दें कि, इस मुकाबले में फोगनिनी ने पहला सेट गंवा दिया था, लेकिन अगले सेट में अपनी सर्विस गंवाने के बाद वापसी करते हुए उन्होंने टाईब्रेकर को मजबूर कर दिया और एक-एक सेट की बराबरी कर ली, इस दौरान अल्काराज ने नेट पर एक आसान पासिंग शॉट गंवा दिया। अल्काराज, बार-बार बदलाव के दौरान काफी उतार-चढ़ाव देखा लेकिन आखिर में उन्होंने तीसरा सेट जीत लिया और मुकाबले में अपनी मजबूत पकड़ बना ली। हालांकि, वह अगला सेट हार गए। हालांकि, उन्होंने अपनी गति बढ़ाई और 3-0 की बढ़त हासिल करने के बाद अपनी मुट्ठियां भींच ली और स्टैंड में एक दर्शक को चिकित्सा की आवश्यकता होने के कारण लंबे ब्रेक के बाद बिना किसी शोर-शराबे के मैच को खत्म कर दिया।

भारत के बांग्लादेश दौरे पर मंडरा रहा संकट, इस कारण रद्द होगी भारत -बांग्लादेश सीरीज?

नई दिल्ली । अगले महीने 17 अगस्त से भारत और बांग्लादेश के बीच 3 वनडे और 3 टी20 सीरीज के तहत मुकाबले खेले जाएंगे। इन सीरीज के लिए भारतीय टीम को बांग्लादेश का दौरा करना है। लेकिन अभी तक इस सीरीज पर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। मौजूदा हालात को देखते हुए दोनों देशों के बीच मौजूदा राजनीतिक हालात के कारण दौरे को लेकर संदेह बरकरार है। इस बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा बयान दिया है और इस पूरे मामले में स्थिति साफ करने की कोशिश की है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने सोमवार को मीडिया को बताया कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई इस दौरे को लेकर अपनी सरकार की मंजूरी मिलने का इंतजार कर रहा है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि दोनों बोर्ड के बीच इस सीरीज को लेकर बातचीत चल रही है और दोनों ही बोर्ड सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अमीनुल इस्लाम ने कहा कि हमारी बीसीसीआई के साथ अच्छी बातचीत चल रही है। जरूरी नहीं है कि ये सीरीज अगस्त-सितंबर में ही हो अगर सरकार द्वारा अभी मंजूरी नहीं मिलती है तो हम भविष्य में किसी और समय इस सीरीज का आयोजन करेंगे।

एक बार फिर चर्चा में काव्या, आईपीएल मैचों को लेकर SRH की मालकिन ने किया बड़ा खुलासा

नई दिल्ली । आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन आईपीएल के दौरान काफी चर्चाओं में रहती हैं। सोशल मीडिया पर उनके कई मीम्स भी वायरल होते हैं। जब कभी भी आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद का कोई भी मैच होता है तो यह मशहूर टीम की मालकिन काव्या मारन लूट लेती हैं। उनकी एक अलग ही फैन फॉलोइंग है जो उनकी एक झलक देखने के लिए बेसब्र रहती है। एक बार फिर काव्या सुर्खियों में है। दरअसल, 2023 में काव्या मारन रातों रात इंटरनेट पर छा गईं जब उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद टीम की कमान संभाली। इसके बाद वह हैदराबाद की टीम को मौजूदा समय में सबसे मजबूत फ्रैंचाइजी बनाने में कामयाब हुईं। उनकी टीम में ट्रैविस हेड, पैट कमिंस, हेनरिक क्लासेन यहां धुरंधर खिलाड़ी शामिल हैं। काव्या स्टेडियम में अक्सर अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए देखी जाती हैं। कई मौकों पर काव्या को SRH ट्रेनिंग रूम में भी मोटिवेशनल स्पीच देते हुए देखा जाता है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान इस खेल के लिए अपने जुनून को लेकर बात की। साथ ही उन्होंने इस पर भी खुलकर बात की कि, वह स्टेडियम में चाहे बॉक्स में बैठी हों तब भी कैमरामैन उन्हें ढूंढ लेता है। इनसाइडस्पोर्ट के साथ बातचीत करते हुए काव्या मारन ने कहा कि, ये मेरी वास्तविक भावनाएं हैं जो आप देखते हैं। हैदराबाद में, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे वहां बैठना पड़ता है। ये तो एकमात्र ऐसी जगह है जहां मैं बैठ सकती हूं, लेकिन जब मैं अहमदाबाद या चेन्नई जाती हूं, और मैं कई फीट दूर, किसी बॉक्स में बैठी होती हूं तब भी कैमरामैन मुझे ढूंढ ही लेता है। इसलिए मुझे समझ में आता है कि ये मीम्स कैसे बन जाते हैं। गौरतलब है कि, सनराइजर्स हैदराबाद ने आखिरी बार साल 2016 में आईपीएल का खिताब जीता था। तब से फ्रैंचाइजी टूर्नामेंट के फाइनल में केवल दो बार साल 2018 और 2024 में ही पहुंच पाई थी।

यश दयाल की कथित गर्लफ्रेंड ने किया नया धमाका, आरसीबी खिलाड़ी की लीक हुई चैट!

नई दिल्ली । आरसीबी के स्टार गेंदबाज यश दयाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गाजियाबाद में इंदिरापुरम की रहने वाली युवती ने यश दयाल के खिलाफ सेक्सुअल हैरसमेंट का केस किया है। युवती ने यश दयाल पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर दोनों की कथित ऑनलाइन चैट का स्क्रीनशॉट भी वायरल हो रहा है। हालांकि, अभी इस वायरल चैट की पुष्टि नहीं हुई है कि ये सच है या गलत। युवती ने यश के खिलाफ मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था। वहीं युवती ने सोशल मीडिया पर लिखा कि, मैंने तुम्हें जाने देने की कोशिश की और सब कुछ भगवान के हाथों में छोड़ दिया, लेकिन जिस तरह से तुम मेरी जैसी लड़कियों को बरगला रहे हो। शायद ये सभी के लिए एक आंख खोलने वाला अनुभव होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा परिवार तुम्हें वफादारी और ईमानदारी के बारे में कुछ सिखाएगा। ये सफलता नहीं है। सच्ची सफलता रिश्तों में स्पष्टता, ईमानदारी और पवित्रता लाती है। लड़कियों के प्रति इस्तेमाल करो और फेंक दो की नीति नहीं। मैं और भी बहुत कुछ कह सकती हूं, लेकिन अब मैं अपने भीतर और गहराई में जाना चाहती हूं। युवती ने आगे लिखा कि, मैं कर्म में विश्वास करती हूं इसलिए मैंने तुमसे अलग होने का फैसला किया, लेकिन अब मुझे अहसास हुआ है तुम जैसे लोगों को सिर्फ कर्म के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। क्योंकि तुम्हें भगवान का डर भी नहीं है। वहीं युवती के हवाले से दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि, मैं 15 दिन तक यश दयाल के घर पर रही। वह मुझे ऊटी की यात्रा पर भी ले गया। मैं कई बार उसके घर गई हूं। उसके परिवार के साथ समय बिताया है। यश दयाल और उसका परिवार शादी का आश्वासन देकर उम्मीदें जगाता रहा।

टेस्ट रिटायरमेंट से पहले नाथन लियोन पूरी करना चाहते हैं अपनी ये इच्छा, भारत से है कनेक्शन

नई दिल्ली । ऑस्ट्रेलियाई स्टार खिलाड़ी नाथन लियोन ने साफ कर दिया है कि वह अभी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट नहीं लेंगे। साथ ही इस दौरान उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा भी बताई है। लियोन ने बताया है कि वह अपने बेहतरीन करियर को विराम देने से पहले भारत में एक टेस्ट सीरीज जीतना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी बार भारत में साल 2004 में टेस्ट सीरीज जीती थी। इसके बाद से टीम ने कुछ मैच जरूर जीते हैं लेकिन टेस्ट सीरीज भारत की मेजबानी में जीतने में अब भी कामयाब नहीं हुई है। 138 टेस्ट मैचों में 556 विकेट ले चुके 37 वर्षीय नाथन लियोन ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल ऑफ स्पिनर हैं। वे भारत के खिलाफ 32 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। इन मैचों में उनको 130 विकेट भी मिले हैं, लेकिन वे कभी भी भारत में टेस्ट सीरीज जीतने का हिस्सा नहीं रहे। ऑस्ट्रेलिया ने 2004-05 में आखिरी बार भारत में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा किया था। इसके बाद से भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में घर पर हार नहीं मिली। जब भारत आखिरी बार अपनी सरजमीं पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज हारा था तो उस समय नाथन लियोन प्रोफेशनल क्रिकेट भी नहीं खेलते थे। क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू ने नाथन लियोन के हवाले से कहा कि, मैंने हमेशा कहा है कि मैं भारत में टेस्ट सीरीज जीतना चाहता हूं। मैं इंग्लैंड में भी टेस्ट सीरीज जीतना चाहता हूं। हमें कुछ सालों में ये मौका मिलेगा लेकिन हमें टेस्ट दर टेस्ट खेलना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि हम वेस्टइंडीज में सब कुछ सही कर रहे हैं। फिर हमें एशेज के साथ घर पर एक बेहतरीन समर सीजन मिलेगा।

एजबेस्टन में कैसा होगा पिच का मिजाज? इंग्लैंड के गेंदबाज क्रिस वोक्स ने खोला राज

बर्मिंघम । इंग्लैंड के तेज गेंदबाजी आक्रमण के सबसे अनुभवी सदस्य क्रिस वोक्स को भारत के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में रनों की बरसात के बाद एजबेस्टन में एक और बल्लेबाजी के लिए माकूल पिच की उम्मीद कर रहे हैं। एजबेस्टन की पिच पर दूसरे टेस्ट से दो दिन पहले काफी घास है लेकिन यहां गर्मी जैसे हालात है और बुधवार को टॉस से पहले घास को काट दिया जाएगा। वोक्स ने कहा, हमने 20 विकेट (लीड्स में) लेने कर अच्छा प्रदर्शन किया। जब वे बल्ले से खेल में दबदबा बनाने लगे, तो हम खुद को मुकाबले में वापस लाने में कामयाब रहे। यह वास्तव में महत्वपूर्ण है और एक अच्छा कौशल है। मुझे यकीन है कि हम एक और ऐसी पिच पर खेलेंगे जो बल्लेबाजी के लिए अच्छी होगी। उन्होंने कहा, अच्छे मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए यह गेंदबाजों के लिए एक और कठिन सप्ताह हो सकता है। हम स्पष्ट रूप से उन चीजों को देखेंगे जो हमने पिछले सप्ताह अच्छी तरह से की थी और उन चीजों को ठीक करने की कोशिश करेंगे जो हमने इस सप्ताह इतनी अच्छी तरह से नहीं कर सके थे। इस 36 साल के तेज गेंदबाज हरफनमौला को हालांकि लीड्स में एक ही विकेट मिला था, लेकिन मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर की गैरमौजूदगी में टीम को उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। 58 टेस्ट मैच खेल चुके वोक्स ने कहा, मैंने इंग्लैंड के लिए जिमी (जेम्स एंडरसन) और ब्रॉडी (स्टुअर्ट ब्रॉड) के साथ बहुत से मैच खेले हैं। उनके बिना खेलना अलग तरह का अनुभव है। नहीं ने कहा, यह मेरे लिए भी एक बढ़िया अवसर है और युवा खिलाड़ियों को थोड़ा ज्ञान देना अच्छा है, जिन्होंने बहुत ज्यादा टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला है। मैं उनसे सीख भी रहा हूं।

वरुण ने चुनी टी20 की ड्रीम प्लेइंग-11, कोहली-रोहित को किया बाहर, बटलर-हेड को बनाया ओपनर

नई दिल्ली । भारत को दो-दो आईसीसी ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने रविचंद्रन अश्विन के यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान अपनी ड्रीम टी20 इलेवन का खुलासा किया है। वरुण ने आश्चर्यजनक रूप से, इस इलेवन में विराट कोहली या रोहित शर्मा को शामिल नहीं किया है। उन्होंने ओपनिंग की जिम्मेदारी जोस बटलर और ट्रैविस हेड को दी है। उनकी ड्रीम प्लेइंग-11 में भारत और वेस्टइंडीज के सबसे ज्यादा तीन-तीन खिलाड़ी है। वहीं, इस इलेवन में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान और श्रीलंका का एक-एक खिलाड़ी है। वरुण ने इस प्लेइंग-11 में उन्हें खिलाड़ियों को शामिल किया है, जिनके साथ या खिलाफ वह खेल चुके हैं। महेंद्र सिंह धोनी और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी इस सूची में शामिल नहीं हैं। वरुण की ड्रीम प्लेइंग-11 में बटलर और हेड को ओपनिंग की जिम्मेदारी दी गई, जबकि तीसरे नंबर पर सूर्यकुमार दिख रहे हैं। चौथा स्थान, जो कि विराट का बैटिंग पोजिशन है, उस पर वरुण ने निकोलस पूरन को चुना है। विकेटकीपर के तौर पर वरुण ने हेनरिक क्लासेन को बाकियों पर तरजीह दी। हालांकि, इस टीम में क्लासेन के अलावा बटलर और पूरन भी विकेटकीपिंग कर सकते हैं। हार्दिक पांड्या और आंद्रे रसेल के रूप में उन्होंने दो पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स चुने हैं। स्पिनर के तौर पर वरुण ने सुनील नरेन और राशिद खान को शामिल किया। वहीं, तेज गेंदबाजी का जिम्मा जसप्रीत बुमराह और मथीशा पथिराना को सौंपा। कुल मिलाकर उनकी टीम संतुलित दिख रही है। नरेन और राशिद के अलावा हेड भी स्पिन बॉलिंग कर सकते हैं। कुल मिलाकर इस टीम में गेंदबाजी के सात विकल्प हैं, जबकि बल्लेबाजी का विकल्प आठ नंबर तक है। हालांकि, सोशल मीडिया पर फैंस कोहली और रोहित को भी इस टीम में शामिल करने की बात कह रहे हैं। वहीं, कुछ फैंस ने रसेल की जगह स्वींद जडेजा को शामिल करने की मांग की। इसके अलावा कुछ फैंस यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा की गैरमौजूदगी पर भी सवाल उठाते दिखे। वरुण ने अश्विन के साथ बातचीत में अपनी संघर्ष की कहानी भी सुनाई। साथ ही बताया कि वह कई चीजों में हाथ आजमा चुके हैं और हर बार दिल की सुनी। वरुण चक्रवर्ती ने बताया कि क्रिकेट में आने से पहले उन्होंने फिल्मों में काम किया था। उन्होंने आर्ट डायरेक्शन टीम में असिस्टेंट के तौर पर काम किया और कभी-कभी फिल्मों में एक्स्ट्रा कलाकार भी बने। वरुण ने मजाकिया अंदाज में कहा कि उनकी पहली कमाई सिर्फ 879 रुपये थी, जो उन्होंने एक फिल्म शूट के दौरान कमाई थी। वरुण ने कहा कि जब वो क्रिकेट में आए तो उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उन्होंने बताया कि उनकी सैलरी में लगभग 4200 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा, आज मैं जो कुछ भी हूं, वो सिर्फ क्रिकेट की वजह से हूं। अश्विन ने भी उनकी मेहनत की तारीफ की और कहा कि वरुण का सफर बाकी युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। वरुण ने अंत में कहा, कोई भी सपना छोटा नहीं होता। अगर मेहनत और लगन हो, तो जिंदगी कभी भी बदल सकती है।

नई खेल नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी, 2047 तक भारत को शीर्ष-5 खेल राष्ट्र बनाना लक्ष्य

नई दिल्ली ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति (एनएसपी) 2025 को मंजूरी दे दी है। यह देश के खेल परिदृश्य को नया आकार देने और खेलों के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल है। नई खेल नीति मौजूदा राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेगी। ये भारत को एक वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने तथा 2036 ओलंपिक खेलों सहित अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्टता के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित करने के लिए एक दूरदर्शी और रणनीतिक रोडमैप प्रस्तुत करेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को एक व्यापक खेलो भारत नीति, 2025 को मंजूरी दे दी है जिसका लक्ष्य 2047 तक भारत को शीर्ष पांच खेल राष्ट्रों में से एक बनाना है। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों पर काफी ध्यान दिया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभा को आगे लाने के लिए यादा ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि नई नीति इसी प्रयास का हिस्सा है। मंत्री ने साथ ही कहा कि इसका दूसरा मुख्य उद्देश्य खेल को जन आंदोलन बनाना है।

मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों पर काफी ध्यान दिया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभा को आगे लाने के लिए यादा ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि नई नीति इसी प्रयास का हिस्सा है।

टेस्ट में 99 के फेर में फंस चुके हैं ये 10 भारतीय बैटर, ऋषभ पंत सात बार हो चुके नर्वस-90 के शिकार

नई दिल्ली । भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच बुधवार से शुरू होगा। इससे पहले टीम इंडिया जमकर तैयारी कर रही है। पहले टेस्ट में हार के बाद सीख लेकर भारत के पुछले बल्लेबाजों से भी बैटिंग प्रैक्टिस कराई जा रही है। शुभमन गिल की अगुआई वाली टीम एजबेस्टन में जब उतरेगी, तो उसकी नजर मैच जीतकर सीरीज को 1-1 से बराबर करने पर होगी। हालांकि, एजबेस्टन में टीम इंडिया का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है। यहां पिछले आठ में से टीम सात मैच हार चुकी है। एक टेस्ट ड्रॉ रहा है। 2022 में जब पिछली बार भारत ने यहां टेस्ट खेला था तो उस मैच में इंग्लैंड ने सात विकेट से जीत हासिल की थी। हालांकि, उस टेस्ट में भारत की ओर से दो शतक लगे थे। ऋषभ पंत और रवींद्र जडेजा ने पहली पारी में क्रमश 146 और 104 रन का स्कोर बनाया था। अब इस टेस्ट में भी दोनों से उसी प्रकार की उम्मीद होगी। पंत के खेलने का स्टाइल अलग है और वह अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से खेल को विपक्षी टीम से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं।

इसी प्रयास में वह कई बार नर्वस-90 के भी शिकार हो चुके हैं। पंत टेस्ट में नर्वस-90 के तीसरे सबसे यादा शिकार होने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं। इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ शीर्ष दो स्थानों पर है। पंत टेस्ट में अब तक सात बार नर्वस-90 के शिकार हुए हैं। इसमें एक बार तो वह 99 के स्कोर पर आउट हुए। ऐसा 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरू टेस्ट में हुआ था। वहीं, सचिन सबसे लंबे प्रारूप में 10 बार नर्वस-90 के शिकार हो चुके हैं, जबकि द्रविड़ नौ बार नर्वस-90 के शिकार हुए हैं। हालांकि, इन दोनों में से कोई 99 के फेर में नहीं फंसा। 99 पर पहुंचने के बाद दोनों ने हमेशा शतक जड़े। सात बार शिकार होकर पंत तीसरे नंबर पर है, जबकि चौथे नंबर पर संयुक्त रूप से तीन बल्लेबाज हैं। इनमें एमएस धोनी, सुनील गावस्कर और वीरेंद्र सहवाग शामिल हैं। ये तीनों पांच-पांच बार टेस्ट में नर्वस-90 के शिकार हुए। वहीं, गौतम गंभीर, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, नवजोत सिंह सिद्धू, दिलीप वेंगसरकर और अजीत वाडेकर चार-चार बार नर्वस-90 के शिकार हो चुके हैं। इसके अलावा मोहिंदर अमरनाथ, चेतेश्वर पुजारा और शुभमन गिल तीन-तीन बार नर्वस-90 के शिकार हो चुके हैं। अब तक कुल मिलाकर 10 भारतीय बल्लेबाज 99 के फेर में फंस चुके हैं। किसी बल्लेबाज के लिए शतक से एक रन पहले आउट होने से यादा बुरा कुछ नहीं है। हालांकि, 10 भारतीय बल्लेबाज इस स्थिति से गुजर चुके हैं। पंकज रॉय टेस्ट में 99 पर आउट होने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं। वह 1959 में नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक रन से शतक से चूक गए थे। वहीं, सौरव गांगुली दो-दो बार 99 के स्कोर पर आउट हो चुके हैं। गांगुली के साथ पहली बार ऐसा 1997 में नागपुर में हुआ था। श्रीलंका के खिलाफ वह एक रन से शतक बनाने से चूक गए थे। इसके बाद 2002 में नॉटिंघम टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ वह 99 रन पर आउट हो गए थे। धोनी भी 2012 में नागपुर में इंग्लैंड के खिलाफ 99 पर आउट हुए थे।